प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 27 – 03 सितम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

# क्या सानन की शिकायत के राजनीतिक अर्थ भी हैं उठने लगी है यह चर्चा

## धूमल-वीरभद्र दोनो की ही सरकारें आयेंगी जांच के दायरे में

**शिमला/शैल।** सेवानिवृत अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन ने वीरभद्र सरकार के कार्यकाल मे हुई कुछ धांधलियों को उजागर करते हुए जयराम ठाकुर की सरकार से इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जांच किये जाने की मांग की है।

स्मरणीय है कि इस बारे में सानन ने जून माह में भी मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर यह मांग की थी। लेकिन तीन माह में इस पत्र पर कोई कारवाई न होने के कारण सानन ने अब एक पत्रकार वार्ता करके इसे सार्वजनिक संज्ञान में ला दिया है। यहां यह विचारणीय है कि सानन और मुख्य सचिव विनित चौधरी एक ही बैच के अधिकारी हैं और जब वीरभद्र शासनकाल मे इनको नज़रअन्दाज करके वीसी फारखा को मुख्य सचिव बना दिया गया था तब इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से एक याचिका डालकर फारखा की नियुक्ति को कैट में चुनौती दी थी। इस चुनौती के परिणामस्वरूप जब कैट ने चौधरी को फारखा के समकक्ष सुविधाएं प्रदान करवा दी थी और चौधरी ने छुट्टी कैन्सिल करके पुन: पदभार संभाल लिया था तब भी सानन को अपनी सेवानिवृति से एक सप्ताह पहले तक छुट्टी पर रहना पड़ा था। उस समय ली गयी तीन माह की छुट्टी का लाभ चौधरी ने मुख्य सचिव बनने के बाद 2018 में सानन को स्टडी लीव के रूप में मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से दिलवाया। इस खुलासे से यह स्पष्ट हो जाता है कि चौधरी और सानन में कितने घनिष्ठ रिश्ते है।

लेकिन जब इतने घनिष्ठ रिश्ते होने के बावजूद चौधरी ने सानन के पत्र पर कोई कारवाई नही की और सानन को आर.एस. गुप्ता को साथ लेकर पत्रकार वार्ता करनी पड़ी तो निश्चितरूप से इस मामले के उस पक्ष को देखना आवश्यक हो जाता है जो अबतक सामने नही आया है। गौरतलब है कि जो पत्र जून में सानन ने मुख्य सचिव को भेजा था उसमें होटल वाईल्ड फ्लावर छराबड़ा और रामपुर के मन्दिर को ग्रांट देने के मामले शामिल नही थे। छराबड़ा के होटल का मामला निश्चित रूप से अन्य मामलों से ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि इसमें प्रदेश सरकार को जो प्रतिवर्ष करोड़ों की आमदनी होनी थी वह नही हो रही हैं। इस होटल प्रकरण में दो – दो बार एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। इस होटल प्रकरण का तो विशेष ऑडिट करवाये जाने की सिफारिश ए.जी. तक ने की हुई हैं। लेकिन आज तक यह ऑडिट नही हो पाया है क्योंकि किसी भी सरकार ने इस आश्य का पत्र कैग को लिखने की हिम्मत नही की है। यह होटल प्रकरण 1993 से 1995के बीच घटा है और इसके बाद दो बार भाजपा तथा दो बार कांग्रेस की सरकारें रह चुकी हैं। ऐसे में जब आज इस मामले में वाकायदा एफआईआर दर्ज करके जांच करवायी जाने की मांग की जा रही है तो निश्चित रूप से इस जांच के दायरे में वीरभद्र के साथ ही धूमल का भी दोनो बार का कार्यकाल रहेगा ही।

इसमें यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस होटल का मामला किसी विशेष राजनीतिक मकसद से उठाया गया है। क्योंकि इस प्रकरण में कैग से विशेष ऑडिट करने के लिये तो जयराम सरकार की ओर से भी कोई कदम नही उठाया गया हैं । वैसे तो सानन स्वयं भी एक समय वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और ऐसे मामलों में जब भी कोई एमओयू हस्ताक्षरित होने की कारवाई होती है तब ऐसे बड़े फैसलों में वित्त सचिव या उसका कोई प्रतिनिधि शामिल रहता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके की इसमें राज्य के हित सुरक्षित रह रहे है या नही। ऐसे मे यह होटल प्रकरण एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है कि यदि इसमें सरकार कोई कारवाई नही करती है तो कोई भी इसे जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय तक ले जा सकता हैं।

सानन के पत्र और अब पत्रकार वार्ता के बाद यह संभावना भी प्रबल हो गयी है सानन के स्टडीलीव और टीडी लेने के मामलों को भी कोई विजिलैन्स और फिर अदालत में ले जा सकता है। क्योंकि स्टडीलीव मामले में जो जवाब विधानसभा में आये एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया है उससे स्थिति और गंभीर हो गयी हैं इस जवाब में स्टडी लीव के जो नियम पटल पर रखे गये हैं उनके अनुसार इस स्टडीलीव के लिये पहले भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था जो नही ली गयी है। फिर स्टडी पर जाने से पहले एक बॉड भरना पड़ता है जो कि नही भरा गया। जबकि मुख्य सचिव विनित चौधरी ने उस समय ऐसी ही छुट्टी जाने पर बॉड भरा था। जिसको लेकर अब एक विवाद भी चल रहा है फिर सानन ने इस स्टडी लीव के बाद जो करीब तीस पन्नों का अपना अध्ययन "Property Titling in India" जो सरकार को सौंपा है उससे सरकार को कितना लाभ हुआ है और इस अध्ययन के आधार पर आगे क्या कदम उठाये गये है। इस बारे में प्रश्न के जवाब में कुछ नही कहा गया है जानकारों के मुताबिक मुख्यमन्त्री को इसका जवाब देना कठिन हो जायेगा क्योंकि सानन को सेवानिवृति के बाद यह स्टडीलीव लाभ उनके अनुमोदन से ही मिला है। नियमों के मुताबिक सानन इस लाभ के पात्र नही थे।

# एच.पी.सी.ए.सोसायटी है या कंपनी मण्डलायुक्त करेंगे फैसला

**शिमला/शैल।** एच.पी.सी.ए. सोसायटी है या कंपनी यह विवाद पिछले छ: वर्ष से भी अधिक सयम से आर.सी. एस. की अदालत में लंबित चला आ रहा है। जबकि एच.पी.सी.ए. को लेकर विजिलैन्स ने कई मामले दर्ज किये और उनके चालान भी अदालत तक पंहुचा दिये है। लेकिन इस प्रकरण में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें सानन आदि कई अधिकारी भी बतौर दोषी नामज़द हैं। उसका चालान जब धर्मशाला के ट्रायल कोर्ट में पंहुचा था और उसका संज्ञान लेकर अदालत ने अगली कारवाई शुरू की थी तब इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देकर इस संद्धर्भ में दर्ज एफआईआर को रद्द किये जाने की गुहार एच.पी.सी.ए. के ओर से लगायी थी उच्च न्यायालय ने इस गुहार को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी थी । इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की कारवाई स्टे कर दी थी। यह मामला अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है।

अब जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और जयराम सरकार ने घोषणा की कि राजनीतिक द्वेष से बनाये गये सारे मामले वापिस लिये जायेंगे तब सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार और एच.पी.सी. ए. दोनों की ओर से सरकार यह कथित फैसला सामने लाया गया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार मामला वापिस लेती है तो उसे कोई एतराज नही होगा। अन्यथा मामला मैरिट पर सुना जायेगा और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। यहां यह भी स्मरणीय है कि इस मामले में एच.पी. सी.ए. ने वीरभद्र को भी उच्च न्यायालय में प्रतिवादी बनाया था और अब सर्वोच्च न्यायालय में भी वह पार्टी हैं । इस मामले मे जब भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुइ है तब तब वीरभद्र के वकील उसमें मौजूद रहे है। वीरभद्र इस मामले में दर्ज एफआईआर वापिस लिये जाने का विरोध करते आ रहे है। संभवता इसी कारण से मामला वापिस लेने की दिशा में सरकार की ओर से कोई व्यवहारिक कदम नही उठाया गया है। एच.पी.सी.ए. को अदालत ने अपने तौर पर मामला वापिस लेने का अवसर दिया था क्योंकि अपील में एच.पी.सी.ए.ही अदालत पंहुची है। इस वस्तुस्थिति में एचपीसीए ने अदालत से ही यह आग्रह किया है कि वही इस पर फैसला करे अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब और क्या आता है इस पर सबकी निगाहे लगी हुई है।

लेकिन इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रदेश सरकारों और उच्च न्यायालयों को विधायकों /सांसदों के आपराधिक मामलों का निपटारा एक वर्ष के भीतर सुनिश्चित करने के लिये विशेष अदालतें गठित करने के निर्देश दिये थे। उस पर क्या अनुपालना हुई है इस पर रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने इस पर केन्द्र सरकार से नाराज़गी भी जाहिर की है। यह विशेष अदालतें मार्च 2018 तक गठित की जानी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय की ओर से इस संद्धर्भ में कोई कदम नही उठाया गया है। इस संद्धर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट जनवरी में भेजी गयी थी। जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में विधायकों /सांसदों के खिलाफ 84 मामले हैं इनमें 20 मामले 2014 से पहले के हैं और 64 मामले उसके बाद के है। सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गयी रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक मामलों की संख्या तो दिखायी गयी है लेकिन इसके लिये विशेष अदालत बनाने की आवश्यकता है या नही इस बारे में कुछ स्पष्ट नही किया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस संद्धर्भ में फिर कड़ा रूख अपनया है। माना जा रहा है कि अदालत के रूख को भांपते हुए सरकार ने एच. पी.सी.ए. का जो मामला आर.सी.एस.के पास लंबित चल रहा था उसे वहां से हटाकर मण्डलायुक्त शिमला को सौंप दिया है।

स्मरणीय है कि पिछले दिनों हुए प्रशासनिक फेरबदल में सरकार ने ऐसे अधिकारी को आर.सी.एस. लगा दिया जो स्वयं एच.पी.सी.ए. में दोषी नामजद है। ऐसे में उस अधिकारी के लिये यह मामला सुन पाना संभव नही था। इसमें दो बार इस मामले की पेशीयां लगी और दोनों बार उसे छुट्टी पर जाना पड़ा। अब उसने सरकार के सामने लिखित में जब यह वस्तुस्थिति रखी तब सरकार ने यह मामला मण्डलायुक्त को सौंप दिया हैं अब मण्डलायुक्त इसमें कितनी जल्दी फैसला देते हैं इस पर सबकी निगाहे लगी है।

# शिमला–कालका रेल ट्रैक के दोनों ओर बनेगी फुलवारी

**शिमला/शैल।** राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन शिमला में रेलवे, वन तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिमला-कालका रेल ट्रैक पर फुलवारी एवं नर्सरी स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करने को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में निर्णय लिया गया कि ट्रैक के हर 5 किलोमीटर पर ऐसी फुलवारी एवं नर्सरी स्थापित की जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि गत दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी भेंट के दौरान विशेष तौर पर शिमला-कालका रेल ट्रैक के दोनों ओर फुलवारी एवं नर्सरी तैयार करने पर बल दिया ताकि पर्यटकों के लिए धरोहर रेल ट्रैक आकर्षण का केंद्र बन सके और फूल व पौधों की बिक्री से रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को सुझाव दिया कि 90 किलोमीटर के इस ट्रैक पर हर 5 किलोमीटर पर एक ऐसी नर्सरी तैयार की जानी चाहिए, जहां ऐसे किस्म के फूल व पौधे उपलब्ध हों, जिन्हें प्रदेश से बाहर भी बिक्री के लिए भेजा जा सके। इस दिशा में टेरीटोरियल आर्मी का भी सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने रेलवे से इस कार्य के लिए स्पॉट चिन्हित करने के लिए कहा। उन्होंने रेलवे द्वारा सोलन जिले के सलोगड़ा में स्थापित नर्सरी के रखरखाव और उनमें विभिन्न किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह रेलवे को पौधे उपलब्ध करवाएं।

रेलवे, वन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर अपने सुझाव दिए।

# भारत सरकार की 25 योजनाओं से 21,18,651 लोग हुए लाभान्वित:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री को राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत करवाया गया।

मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि अभी तक भारत सरकार की 25 योजनाओं के अन्तर्गत 21,18,651 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। हालांकि नव-निर्मित आवासों तथा परिसरों को प्रत्येक वर्ष लगभग 40 हजार कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत 6101 घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और 7055 कनेक्शन अक्तूबर, 2018 तक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी नेतृत्व निर्माण घटक के अन्तर्गत 348 घरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 2000 घर निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत योजना आरम्भ होने से लेकर अभी तक 14110 परिवारों को घर प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त, 2018 तक एकत्र डाटा के अनुसार योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण में हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य है।




जय राम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत राज्य में 74608 लोगों को लाभान्वित किया गया है और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल न होने वाले लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में एम्स के निर्माण के लिए 681 बीघा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और 666 बीघा भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 503786 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं और कार्यक्रम को राज्य में गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है तथा मार्च, 2019 तक लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुषमान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य में अभी तक 525000 लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, वन रैंक वन पैंशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पैंशन योजना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डीडीयू राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल योजना, आयुष, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, स्टैंडअप इण्डिया योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा हुनर से रोजगार तक योजनाओं की प्रगति बारे में भी अवगत करवाया।भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, केन्द्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया।

# हिमाचल में खुलेंगी भारत पोस्ट पैमेंट बैंक की 12 शाखाएं

**शिमला।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली से देश के लिए भारत पोस्ट पैमेंट बैंक का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऐतिहासिक गेयरी थियेटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लिए भारत पोस्ट पैमेंट बैंक का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों की योजना है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि इससे समाज के कमजोर वर्गों का आर्थिक उत्थान भी सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से लाभार्थी को मनरेगा मजदूरी, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं के भुगतान का लाभ सीधे हस्तांतरण के माध्यम प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थी बिलों का तत्काल भुगतान करने और उसे भारत पोस्ट पैमेंट बैंक खाते से भेजने व प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो उन्हें प्रमुख बैंकों और आश्वासन कम्पनियों से ऋण व बीमा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लाखों भारतीयों की अभी भी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नही है तथा भारत पोस्ट पैमेंट बैंक देश के असम्बद्ध और अधीन बैंकों को मूल बैंकिग सुविधाओं की प्राप्ति में सहायता करेगा।

उन्होंने कहा कि देशभर में 1. 54 लाख से अधिक डाकघरों में भारत पोस्ट पैमेंट बैंक आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल चैनलों की श्रृंखला में विश्व का सबसे सुलभ बैंक होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 12 ज़िलों में भारत पोस्ट पैमेंट बैंक की 12 शाखाएं खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी नौ डाक खण्डों के अंतर्गत 2790 डाकघरों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की सफलता के लिए डाक विभाग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा ने कहा कि भारत पोस्ट पैमेंट बैंक बैंकिग क्षेत्र में मील पत्थर साबित होगा, क्योंकि डाक सेवा की पहुंच राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी हैं उन्होंने कहा कि अब लोगों को घर-द्वार पर बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

निदेशक डाक सेवा हिमाचल प्रदेश ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य का स्वागत किया।


**HIMACHAL PRADESH**
**IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT**
***CORRIGENDUM**

E-tender (ID - 2017_HPIPH_18936_1) of Prov. and commissioning of UV-Vis Spectrophotometer and thermo reactor at Chamba, Hamirpur and Reckongpeo called vide this office letter No. IPHDS-CB-EA-I-Tender/2016-17-13492-97 dated 27.12.2017 due for opening on 19.01.2018 at 11.30 AM is hereby cancelled due to technical/ administrative reasons.

**Adv. No.-2051/18-19** **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**



**HIMACHAL PRADESH**
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
**'NOTICE INVITING TENDERS'**

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division HP.PWD., Palampur on behalf of the Governor of H.P for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on 25.09.2018 up to 11.00 AM. And the same shall be opened on the same day at 11.30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on 24.09.2018 up to 4.00 P.M and the application for issue of tender form shall be received on 22.09.2018 up to 12.00 noon.

The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

| Sr.No. Nameof work | Estimated Cost | Earnest Money | Time Limit | Cost of Tender Form |
|---|---|---|---|---|
| 1. Construction of D/Shala Yol Dadh Palampur road Km. 15/00 to 33/00. (SW:- Earth filling at Rd 0/00 to 0/50 and Edge wall with U-Shape drain at Rd 0/00 to 0/070 and 300mm dia H.P. culvert at Rd 0/015). | 2,66,762/- | 5400/- | Three Months | 350/- |
| 2. C/O link road from Pira to Hoda. (SW:- P/L soling WBMG-I (90-45mm) at Rd 0/750 to 1/500). | 2,55,138/- | 5100/- | Three Months | 350/- |
| 3. C/O Parour Dharot road. (SW:- C/O R/Wall at Km. 1/300 to 1/320). | 2,18,005/- | 4400/- | Three Months | 350/- |

**Terms & Conditions:-**
**Following documents should accompany the application for tenders.**
1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand . Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

**Adv. No.-2090/18-19** **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**



**OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER JAISINGHPUR DIVISION**
**H.P. PUBLIC WORKS DEPARTMENT, JAISINGHPUR 176095**
**TENDER NOTICE**

**1. The Executive Engineer, Division, HP.PWD. Jaisinghpur 176095** on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the online bids on item rate, electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved Contractors/ Firms registered with HPPWD, Department.

| Sr.No. Name of Work | Estimated Cost in Rs | EMD in Rs | Time Limit | Form No | Cost of bidding Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Improvement of Black Spot on Hamirpur Sujanpur Thural Maranda road in Km. 24/135 to 45/525(SH:- C/o 900mm dia Hume pipe culverts & R/ walls at RD 36/720 to 36/786) on extended portion | Rs.12,58,041/- | Rs.25,200/- | Six Month | 6&8 | 500/- |

**2.Availability of Bid Document and mode of submission:** - The bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website https://hptenders.gov.in Bidder would be required to register in website which is free of cost. For submission of bids , the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD. May obtain the same from the website:- https://hptenders.gov.in . Digital Signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized Cas can use the same in this tender.

**3.Key Dates.**

| | |
|---|---|
| 1. Date of Online Publication. | 17.09.2018 10.00AM |
| 2. Document Download Start and End Date. | 17.09.2018 10.30AM upto 29.09..2018 03.00 PM |
| 3. Bid submission start and end date | 17.09.2018 10.30AM upto 29.09..2018 03.00 PM |
| 4. Physical Submission of EMD And Cost of Tender document | 01.10.2018 upto 10.30 HRS |
| 5. Date of Technical Bid opening ,Evaluation of technical Bid | 01.10.2018 11.00 HRS |
| 6. Date of Financial Bid Opening | 08.10.2018 11.30 HRS |

**4 TENDER DETAILS.**
The Tender documents shall be uploaded online in 2 Cover.
i) **Cover1:** Shall contain scanned copes of all **"Technical Documents/ Eligibility information".**
ii) **Cover 2:** Shall contain **"BOQ/Financial Bid"** where contractor will quote his offer for each item.

5. **Submission of Original Documents:-** The Bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/ Earnest Money Deposit (EMD) and other technical documents in the o/o Executive Engineer HPPWD Division Jaisinghpur as specified in Key dates Sr.No.4 on Tender Opening Date, failing whi,,ch the bids will be declared non-responsive.

6. **BID OPENING DETAILS:** The bid shall be opened on 01.10.2018 at 11.00 HRS in the office of the Executive Engineer, Jaisinghpur Division HP PWD Jaisinghpur HP. By the authorized officer. In their interest the tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

**Adv. No.-2050/18-19** **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**



**शैल समाचार**
**संपादक मण्डल**

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
भेपेश
रीना

# राष्ट्रीय राजमार्गों का 64 हजार करोड़ कब देगी मोदी सरकार

## ❖ केंद्रीय परियोजनाओं के लिये केन्द्र से कितना धन मिला है सरकार श्वेत पत्र जारी करे

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश से जुड़े बड़े प्रोजैक्टों को धरातल पर लाने में केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। केंद्र सरकार द्वारा की गई तमाम घोषणाएं हकीकत में नही बदली हैं। पिछले चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री, नीतिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 64 हजार करोड़ रुपये की लागत से करीब 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की थी। लेकिन इस मसले में अभी तक फूटी-कौड़ी भी हिमाचल प्रदेश के कोष में नही आई है और न ही किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का टैंडर हो पाया है। प्रतिपक्ष के नेता, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार के महज 6 महीने बचे हैं तो क्या केंद्र या राज्य सरकार यह बता पाएगी कि यह 64 हजार करोड़ रुपये कब हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। उन्होने कहा कि इसके लिए सैद्धांतिक पत्र और हवाई किले बनाकर बात नही चलेगी। एक बहुत बड़ा ऐलान राज्य विधान सभा चुनाव से ठीक पहले किया गया था, उसे पूरा करते हुए यह पैसा हिमाचल को एक पैकेज के तहत दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री, जय राम ठाकुर ने 69 नैशनल हाईवेज को 70 में बदल दिया है क्योंकि उन्होनें कुल्लू जिला के आनी में नैशनल हाईवे बनाने बारे विधान सभा में बयान दिया है। राज्य के सांसद गाहे-बगाहे कोई-न-कोई सैद्धांतिक अनुमतियों का पत्र अखबारों में जारी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता की आंखों में धूल नही झोंकी जा सकती। राज्य जानना चाहता है कि क्या चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल को इन 70 नैशनल हाईवेज का पैसा जारी करेगी?

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी कई सुरंगों और पुलों को बनाने की घोषणाएं भी की गई है। लेकिन जो घोषणाओं का आकार है, क्या उतना बजट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के पास उपलब्ध है? इस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। उन्होने कहा कि सवाल में यह साफ हो गया है कि करीब 4500 किलोमीटर लम्बे नैशनल हाईवेज महज सैद्धांतिक मंजूरियों के पालने में ही झूल रहे हैं। आलम तो यह है कि बरसात से हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के नुकसान के लिए

भी कोई पुख्ता कदम नही उठाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर लगभग तमाम केंद्रीय प्रोजैक्ट घोषणाओं और सवालों तक ही सीमित है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय की बड़ी-बड़ी दुहाइयां देने के बावजूद भी अभी तक इसके निर्माण की आधारशिला नही रखी गई है और यही हाल केंद्रीय प्रायोजित AIIMS अस्पताल, IIIT और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है। विधान सभा चुनाव से ठीक पहले अक्तूबर महीने में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर इनके शिलान्यास के पत्थर रख दिए लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद कोई भी टैंडर अभी तक इनका सम्भव नही हुआ है।

उन्होने कहा कि प्रदेश में रेल लाइनों को लेकर भी बड़े-बड़े एलान किए गए लेकिन अभी तक कोई भी प्रगति रेल को लेकर नही हुई है। यही स्थिति ऊना के पी.जी.आई. संस्थान को बनाने को लेकर भी है। अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब आनन-फानन में लीपापोती की जा रही है। उन्होने दलील दी की औद्योगिक पैकेज को लेकर भी हिमाचल प्रदेश से भेदभाव किया गया और उत्तरी-पूर्व राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को पैकेज नही दिया गया और इसमें कटौती कर दी गई।

उन्होने कहा कि अब हवाई पट्टी के निर्माण को लेकर भी घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन सरकार को यह बताना होगा कि कितने पैसे इसके निर्माण के लिए या मौजूदा पटियों के विस्तार के लिए हिमाचल को मिले हैं? जबकि सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारअभी तक भी कर्जा उठा रही है। जनता के बीच जाकर ऐसे हवाई ऐलान कर रहे हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने उनका खजाना विभिन्न योजनाओं से भर दिया है।

सच्चाई तो यह है कि स्वां चैनेलाइजेशन की परियोजना, जो 922 करोड़ रुपये की थी और छोंछ खड्ड योजना के कार्य केंद्र सरकार ने राजनैतिक इशारे पर रोक दिए हैं। अखबारों में लगातार एलान हो रहा है कि यह बचा हुआ पैसा हिमाचल को मिल गया है लेकिन कोई पैसा हिमाचल सरकार की किट्टी में नही आया है। विभिन्न संस्थानों से कर्जे लेकर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां जताने की कोशिश न करें बल्कि इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे कि केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर कितनी राशि हिमाचल प्रदेश के खजाने में आई है अन्यथा रोज ही सैद्धांतिक अनुमतियों का ढिंढोरा पीटने से भाजपा की नैयया पार होने वाली नही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में यह हवाई घोषणा एक बहुत बड़े मुद्दे का रुप धारण करेगी।

# जयराम सरकार में आढ़तियों की लूट से बेहाल बागवान: सिंघा

**शिमला/शैल।** एकमात्र वामपंथी विधायक राकेश सिंघा ने विधानसभा में सेब मंडियों में आढ़तियों की ओर से बागवानों के साथ मचाई जा रही लूट का मसला उठाते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नियम 62 के तहत चर्चा करते हुए सिंघा ने कहा कि 2002 में प्रदेश कृषि, बागवानी उत्पाद विपणन विकास व नियमन अधिनियम पारित हुआ था।

इस अधिनियम का इन दिनों ठियोग, रोहडू, पराल व ढली मंडियों में सरेआम उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जयराम ठाकुर सरकार इस लूट-खसूट को लेकर गंभीर नही हैं व आढ़तियों को लूट के लिए खूला छोड़ा हुआ हैं।

उन्होंने कहा कि सेब की कीमत वजन के हिसाब से मिलनी चाहिए लेकिन आढ़ती पेटी के हिसाब से कीमत दे रहे हैं। यह अधिनियम का खुला उल्लंघन है व बागवानों की मेहनत का मजाक है और सरकार चुप बैठी है। पेटी का कीमत निर्धारित होने के बाद आढ़ती उसकी कीमत को मनमर्जी से कम कर रही है। जबकि एक बार नीलामी हो गई तो उसकी कीमत को कम नही किया जा सकता। यहां यह हो रहा है कि साढ़े चौदह सौ रुपए प्रति पेटी के हिसाब से नीलामी हुई है तो आढ़ती इसके चौदह सौ से साढ़ तरह सौ रुपए बागवानों को दे रहे हैं। यह खुली लूट है। इसकी कानून कतई अनुमति नही देता हैं।

उन्होंने कहा कि आढ़ती गाड़ी के भाड़े को भी जो किसान ने पहले ही गाड़ी वाले को अदा कर दिया है, उस राशि को भी काट लेता है। यही नही सेब को उतारने व चढ़ाने की एवज में पांच से बीस रुपए काटे जा रहे हैं जबकि अधिनियम के मुताबिक पांच रुपए से ज्यादा नहीं काटे जा सकते हैं। सिंघा ने इलजाम लगाया कि इस में से पल्लेदार को तीन से साढ़े तीन रुपए तक ही दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शोधी व परवाणु में बेरियर लगा रखे हैं वहां मार्किटिंग फीस के नाम पर चूंगी काटी जा रही है। जबकि यह कभी की खत्म हो गई है।

सिंघा ने कहा कि जब सेब की

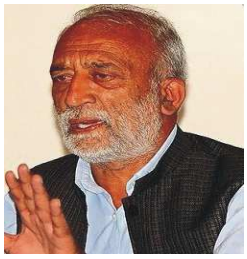

नीलामी हो गई तो बागवानों को तुरन्त पैसा मिल जाना चाहिए। कम से कम पंद्रह दिन बाद तो मिल ही जाना चाहिए लेकिन यहां पर महीनों ही नहीं कई मामलों में साल के बाद भी पैसा नहीं मिला है। उन्होने सरकार से इस लूट से बागवानों को निजात दिलाने की मांग की।

चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा कि इस तरह के मामले मार्किटिंग यार्ड के बाहर से समाने आ रहे हे। विभाग ने छह एफआइआर दर्ज की है और एक लाइसेंस रद्द कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों के अलावा पुलिस को भी शिकायतों पर तुरंत कारवाई करने के आदेश दिए है। वह खुद भी मंडिया का लगातार दौरा कर रहे है।

मारकंडा ने कहा कि मंडियों में वजन के हिसाब से कीमत अदा करने का फरमान जारी किया गया है। लेकिन बागवान आढ़तियों से सौदा कर लेते हैं व वजन के बजाय पेटियों के हिसाब से ही कीमत ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी चिंतित है लेकिन साथ ही कदम भी उठाए जा रहे है। पल्लेदारी के पांच रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा सकते । अगर कहीं ऐसा है तो कर्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा व सरकार बागवानों व किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है।

# लखवार परियोजना में हिमाचल को मिलेगा 3.15 प्रतिशत पानी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में ऊपरी यमुना जलाश्य में 4000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली बहुउद्देशीय परियोजना लखवार (एमपीपी) के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित समारोह में भाग लिया। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में छः राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लखवार बहुद्देशीय परियोजना के लिए यमुना नदी पर 330 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) की जीवंत भण्डारण तथा 330 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले 204 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से 79 एमसीएम स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जो छः राज्यों में पानी की कमी से निजात दिलाने में मददगार होगी। इससे गैर-मानसून के दौरान यमुना नदी के प्रवाह में 65 प्रतिशत की वृद्धि और 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के तहत आएगा। जल घटक परियोजना की 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राज्यों द्वारा उन्हें 12.05.1994 के समझौता ज्ञापन के आधार पर आवंटित जल हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर इन

राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना के विद्युत घटक की लागत का वहन उत्तराखण्ड द्वारा किया जाएगा और वे ऊर्जा उत्पादन का लाभ प्राप्त करेंगे। परियोजना का निर्माण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 54 माह के भीतर किया जाएगा तथा परियोजना के कार्यों की निगरानी अप्पर यमुना नदी बोर्ड द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को हिस्से में रूप में 3.15 प्रतिशत पानी मिलेगा और तदानुसार परियोजना के जल घटक का राज्य हिस्से के रूप में 8 करोड़ रुपये का योगदान करेगा। उन्होने कहा कि यमुना नदी तथा इसकी सहायक नदियों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आने वाली टोंस और गिरि नदी पर कुल तीन मुख्य भण्डारण परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें 330 एमसीएम लाइव स्टोरेज की बहुद्देशीय लखवार परियोजना, टोंस नदी से 300 मेगावॉट बिजली उत्पादन और हिमाचल प्रदेश में 498 एमसीएम लाइव भण्डारण वाली हिमाचल प्रदेश की रेणुका परियोजना तथा गिरी नदी पर 40 मेगावॉट बिजली उत्पादन परियेजनाएं शामिल हैं। केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# युवाओं के लिये अटल हिमाचल स्वावलम्बन अभियान शुरू करेगी सरकार

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार बेरोज़गार युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने व आजीविका प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर हिमाचल प्रदेश सरकार की कौशल स्तरोन्यन पहल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि 40 लाख तक निवेश पर संयंत्र व मशीनरी के लिए 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को 40 प्रतिशत पूंजी अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 40 लाख के ऋण पर तीन वर्षों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा प्रदेश में क्रियाशील औद्योगिक इकाई की मांग के अनुरूप युवाओं का कौशल स्तरोन्यन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इससे न केवल उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि स्वरोजगार को नया खाका भी तैयार होगा। प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल स्तरोन्यन के लिए अटल हिमाचल स्वावलम्बन अभियान आरम्भ करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश कि विभिन्न योजनाओं को कौशल विकास के अन्तर्गत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन योजनाओं के बेहतर परिणाम सुनिश्चित हो सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्किल मैप्स एवं स्किल गैप सर्वेक्षण की पहल की जाएगी ताकि कौशल स्तरोन्यन कार्यक्रमों के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कौशल स्तरोन्यन केन्द्र स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाएगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जयकान्त सिंह ने कौशल स्तरोन्यन कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तुति दी।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के बेहतरी के लिए सभी कौशल स्तरोन्यन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएगी।

जब कार्यो की अधिकता हो, तब उस कार्य को पहले करें, जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। .....चाणक्य

## सम्पादकीय

# आरबीआई की रिपोर्ट से सरकार की विश्वनीयता पर उठे सवाल

नवम्बर 2016 को लागू की गयी नोटबंदी के बाद पुरानी मुद्रा के 500 और 1000 रूपये के नोटों का चलन बन्द कर दिया गया था। इस आदेश के साथ ही जनता को पुराने नोटों को नये नोटों से बदलने के लिये समय दिया गया था। इस दिये गये समय में कितने पुराने नोट वापिस बैंको में जमा हुए और अन्तत: रिजर्व बैंक के पास पंहुचे इसकी अब 21 माह बाद फाईनल रिपोर्ट आ गयी है। आरबीआई ने संसदीय दल को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि देश में पुरानी 500 और 1000 की मुद्रा के कुल 15.44 लाख करोड़ के नोट थे। जिनमें से 15.31 लाख करोड़ के नोट वापिस आ गये हैं जो कि 99.3% होते हैं। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि इन वापिस आये नोटों में नेपाल और भूटान से आये नोट शामिल नही हैं। आरबीआई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरानी मुद्रा के लगभग सौ प्रतिशत ही नोट वापिस आ गये हैं।

इससे सबसे पहले यह सवाल उठता है कि जो प्रचार हो रहा था कि देश में कालेधन की समानान्तर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गयी है वह प्रचार निराधार था। स्वामी राम देव जैसे कई लोग आये दिन लाखो करोड़ के कालेधन के आंकड़े देश के सामने रख रहे थे। आज आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद यह सारा प्रचार एक सुनियोजित षडयंत्र लग रहा है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि यह प्रचार शायद प्रायोजित था। क्योंकि जब नोटबन्दी की घोषणा की गयी थी तब प्रधानमन्त्री ने नोटबन्दी का यही तर्क दिया था कि यह कदम कालेधन को रोकने के लिये उठाया गया है। क्योंकि कालेधन का निवेश आंतकवाद के लिये हो रहा था। प्रधानमन्त्री ने जब यह तर्क देश के सामने रखा था तब देश की जनता ने उन पर विश्वास कर लिया था। इसी विश्वास के कारण लोग इस फैसले के विरोध में लामबन्द होकर सड़कों पर नही उतरे थे। देश को लगा था कि जब प्रधानमन्त्री इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास कालेधन और उसके निवेश को लेकर ठोस जानकारियां रही होंगी। उनके वित्तमन्त्री ने पूरी तस्वीर उनके सामने रखी होगी। लेकिन आज यह सब पूरी तरह गलत साबित हुआ है। क्योंकि इसी का दूसरा पक्ष तो और भी घातक हो जाता है कि क्या यह कदम आम आदमी की कीमत पर कालेधन को सफेद बनाने के लिये उठाया गया था। क्योंकि आज तक यह नही बताया गया है कि कितना कालाधन पकड़ा गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद प्रधानमन्त्री, वित्तमन्त्री और उनकी सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

आरबीआई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस फैसले से देश को दो गुणा नुकसान हुआ है। क्योंकि मुद्रा की प्रिंटिग का एक नियम है। किसी भी देश की करेंसी उस देश के जीडीपी के अनुपात में छापी जाती है भारत में यहअनुपात 10.6 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक इस संतुलन को बनाये रखता है। लेकिन भारत में जब से सरकारी क्षेत्र में निजिक्षेत्र का प्रभाव बढ़ा है तक से सरकारी बैंक खतरे में पड़ गये हैं और विजय माल्या,मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे प्रकरणों ने इस खतरे को पुख्ता भी कर दिया है। इस संद्धर्भ मे आरबीआई की वेबसाईड पर पड़े मनी स्टोक के आंकड़े यह बताते है कि अप्रैल 2012 में परिचलन में कुल 11,08,232 करोड़ रूपये थी जिसमें से बैंकों की तिजोरी में 43,377 करोड और जनता की जेब में 10,64,855 करोड़ थी। जुलाई 2016 में परिचलन 17,36,177 करोड़ रूपये थी जिसमें से बैंको के पास 75034 करोड़ रूपये और बैंको से बाहर जनता की जेब 16,61,143 करोड़ रूपये थे। आरबीआई के इन आंकड़ो को शायद यह मान लिया गया कि देश में इतना कालाधन है जिसे नोटबंदी से एक ही झटके में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में यह सब बैंकों पर कम होते जा रहे विश्वास का परिणाम था। नोटबंदी के बाद जिस तरह से सरकारी बैंकों का घाटा सामने आता जा रहा है उससे यह भरोसा और कम हो रहा है। इसी के कारण जहां 15.44 की पुरानी करेंसी को बदलना पड़ा है उसी के साथ उतनी ही नयी करेंसी को छापना पड़ा है। इस दोहरे नुकसान के कारण क्या आज करेंसी के मुद्रण में आरबीआई 10.6 प्रतिशत के अुनपात को बनाये रख पाया है या नही इसको लेकर अधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नही आया है।

नोटबन्दी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा आघात पंहुचा है अब इस तथ्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। अर्थव्यवस्था तो देश की बुनियाद होती है। जब बुनियाद एक बार हिल जाती है तो उसे संभलने में समय लगता है। आज देश इस स्थिति से गुज़र रहा है। इससे प्रधानमन्त्री की अपनी समझ और विश्वसनीयता दोनों पर जो प्रश्नचिन्ह लगा दिया है उसके परिणाम घातक होंगे। क्योंकि यदि इस असफलता को सीधे और ईमानदारी से स्वीकारने की बजाये कुछ और मुद्दे खड़े करके देश का ध्यान बांटने का प्रयास किया जायेगा तो शायदे वह स्वीकार्य नही होगा।

# कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋण में 64 करोड़ हुआ एनपीए

**शिमला/शैल।** कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक ने पिछले तीन वर्षो में 547 ईकाईयों को 174,06,28,742. 68 का ऋण दिया है जिसमें से 64,30,47,236.02 रूपये एनपीए हो चुका है। यह ऋण 1-4-2015 से 31-3-2018 के बीच दिया गया यह जानकारी विधानसभा के इस मानसून सत्र में हमीरपुर के विधायक नरेन्द्र ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में दी गयी है। इस प्रश्न पर सदन में आयी चर्चा के दौरान मन्त्री विक्रम ठाकुर ने यह आश्वासन दिया है कि इस ऋण को दिये जाने की पूरी जांच करवाई जायेगी। मन्त्री ने सदन को यह भी बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे साधन संपन्न लोग भी बैंक का ऋण वापिस नही कर रहे हैं। प्रदेश के सहकारी बैंको को लेकर बजट सत्र में भी एक सवाल आया था। उसमें पूछा गया था कि इन बैंकों का एनपीए कितना हो चुका है। इस प्रश्न के उत्तर में आयी जानकारी के अनुसार प्रदेश के दस सहकारी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 938.27 करोड़ था। जिसमें कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक का एनपीए 560. 60 करोड़ था।अन्य सहकारी बैंकों की स्थिति यह थी-राज्य सहकारी बैंक 250.48 करोड़ ,जोगिन्द्रा सहकारी बैंक 52.66 करोड़, हि.प्र. राज्य सहकारी सहकारी विकास बैंक 29.50 करोड़, शिमला अर्बन सहकारी बैंक 2.04 करोड़, परवाणु अर्बन सहकारी बैंक 6. 06 करोड़, मण्डी अर्बन सहकारी बैंक 1. 32 करोड़, बघाट अर्बन सहकारी बैंक 20.99 करोड़ और चम्बा अर्बन सहकारी बैंक 023 करोड़।

प्रदेश के सहकारी बैंकों की इस स्थिति से प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन पर ही गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं क्योकि हर छोटा बड़ा बैंक एनपीए का शिकार है। कांगड़ा बैंक ने 547 उद्योग ईकाईयों को 174 करोड़ ऋण 1-4-2015 से 31-3-2018 के बीच दिया है। जिसमें आज 64 करोड़ से अधिक का एनपीए हो चुका है। स्मरणीय है कि जब कोई ऋण तय समय सीमा के भीतर अदा नही हो पाता है तब वह एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। इसलिये इसमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि ऋण की वापसी करने की नीयत ही नही हैं या फिर बाजिव कारणों से ऋणधारक ऋण को चुका नही पा रहे हैं। यह जांच से ही सामने आयेगा क्योंकि मन्त्री जब यह कहे कि साधन संपन्न लोग भी अदायगी नही कर रहे हैं तो स्थिति एकदम बदल जाती है।

कांगड़ा बैंक के सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र से लेकर अब तक इसमें से केवल 28 करोड़ की ही रिकवरी बढ़ी है। बैंक ने जिन उद्योग ईकाईयों को ऋण दिया है उस सूची पर नज़र डालने से यह सामने आता है कि दर्जनों इकाईयां एसी हैं जिन्हें एक ही दिन में दो-दो बार ऋण दिया गया है ऐसा क्यों किया गया एक ही बार क्यों प्रोपोजल क्यों नही बनाए गये यह जांच का विषय बनता है।

अब जब मन्त्री ने सदन में जांच का आश्वासन दे दिया है उसके बाद अब इस पर निगाहें लगी हुई है कि वास्तव में इस जांच के आदेश कब होते हैं और विजिलैन्स इस जांच में कितनी गंभीरता दिखाती है। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमन्त्री और मुख्य सचिव विजिलैन्स को सहकारी बैंक में हुई भर्तीयों के मामले की जांच करने के आदेश कर चुके हैं लेकिन इस पर अभी तक कोई कारवाई शुरू नही हुई है। ऐसे में यह आशंका बराबर बनी हुई है कि इस मामले का अंजाम भी कहीं इसी तरह का न हो।

# यह है ऋण धारकों की सूची

**Account wise Detail of Loans sanctioned to industrial units in 2015-2016 (01-04-2015 to 31-03-2016)**

| Sr. No. | Name of Borrower | Amount Sanctioned | Date of Sanction | Outstandin Amount | Status of Account (Standard or NPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sh Naresh Kumar Dhiman | 475000 | 15/03/16 | 349,360.00 | NPA |
| 2 | Kimat Ram | 50000 | 19/11/2015 | 34,174.00 | NPA |
| 3 | Pushap Ram | 380000 | 02/09/15 | 277,778.00 | NPA |
| 4 | NEEL CHAND | 450000 | 01/06/15 | 185,823.00 | NPA |
| 5 | Mrs. DECHEN DOLMA | 100000 | 11/02/15 | 70,465.00 | NPA |
| 6 | Mr. TANZIN DEKYOG | 50000 | 03-11-2015 | 38,231.00 | NPA |
| 7 | Raj kumar | 250000 | 08/02/16 | 183,423.00 | NPA |
| 8 | Chaitnya | 285000 | 14/08/2015 | 120,848.00 | NPA |
| 9 | Sh Archit Thakur | 125000 | 08/07/15 | 115,113.00 | NPA |
| 10 | M/S Crest Steel Una Pvt. Ltd. | 50000000 | 10/12/15 | 305,838,516.00 | NPA |
| 11 | M/S Crest Steel Una Pvt. Ltd. | 50000000 | 10/12/15 | 60,055,638.00 | NPA |
| 12 | Sh KuldeepSiingh | 200000 | 30/10/2015 | 147,399.48 | NPA |
| 13 | HOTEL RS BALVEDRE | 36500000 | 31/10/15, | 38,656,796.00 | NPA |
| 14 | HOTEL RSBALVEDRE | 19000000 | 08/04/15 | 18,497,089.00 | NPA |
| 15 | Sh Ashok Kumar | 50000 | 20/05/15 | 11,310.00 | NPA |
| 16 | Mrs. Veena Sharma | 500000 | 07/08/15 | 500,246.99 | NPA |
| 17 | M/S VC Foods | 2240000 | 05/05/15 | 2,167,423.00 | NPA |
| 18 | Sanjeev | 190000 | 26/08/15 | 152,566.00 | NPA |
| 19 | Sameer Engineers | 1000000 | 20/11/15 | 657,189.00 | NPA |
| 20 | Smt Manju Devi | 350000 | 13/05/15 | 176,381.00 | NPA |
| 21 | Shree Ganesh Traders | 1100000 | 10/06/15 | 1,055,480.00 | NPA |
| 22 | Kulwant Kumar | 850000 | 03/01/16 | 855,763.00 | NPA |
| 23 | Govind Ram | 427500 | 04/09/15 | 357,126.00 | NPA |
| 24 | CHANDA THAKUR | 120000 | 27/06/2015 | 158,094.00 | NPA |
| 25 | CHANDA THAKUR | 100000 | 27/06/2015 | 111,392.00 | NPA |
| 26 | Vinay Agro Industries | 360000 | 30-10-2015 | 393,769.00 | NPA |
| 27 | Vishal Industry | 3000000 | 11/05/15 | 3,003,166.00 | NPA |
| 28 | Mrs. RADHA DEVI | 80000 | 18/06/2015 | 55,829.55 | NPA |
| 29 | | | | **434,226,389.02** | |
| 30 | BEASA DEVI | 3000000 | 23/09/2015 | 107,919.00 | Standard |
| 31 | KK STELL FEBRICATION | 2000000 | 10/03/16 | 148,141.00 | Standard |
| 32 | Mr. CHHERINGANGCHUK | 250000 | 10-11-2015 | 46,719.00 | Standard |
| 33 | Mr. DEEPAK KUMAR | 950000 | 17-11-2015 | 591,174.00 | Standard |
| 34 | THE BANDROL SCWOMEN HL H | 500000 | 20/01/2015 | 444,872.00 | Standard |
| 35 | Mr. SHER SINGH | 50000 | 26-06-2015 | 9,594.00 | Standard |
| 36 | Mrs. SURDERSHNA DEVI | 283000 | 21-09-2015 | 150,738.00 | Standard |
| 37 | Niranjan Agro Industry | 2000000 | 22/01/2016 | 1,921,997.00 | Standard |
| 38 | KRISHNA DEVI | 40000 | 29.05.15 | 7,081.00 | Standard |
| 39 | LATA | 40000 | 13.10.15 | 10,532.00 | Standard |
| 40 | Mr. PANA LAL | 80000 | 28-12-2015 | 39,016.00 | Standard |
| 41 | M/S Kashmiri FoodProducts | 980000 | 15/12/2015 | 794,690.00 | Standard |
| 42 | Mrs. SURDERSHNA DEVI | 317000 | 21-09-2015 | 316,211.00 | Standard |
| 43 | Mr. CHHERING ANGCHUK | 150000 | 10-11-2015 | 22,057.00 | Standard |
| 44 | Mr. DEEPAK KUMAR | 50000 | 17-11-2015 | 49,900.00 | Standard |
| 45 | Om Parkash | 950000 | 24/09/2015 | 605,535.00 | Standard |

शेष पृष्ठ 5 पर.....

# कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋण

.....पृष्ठ 4 का शेष

| Sr. No. | Name of Borrower | Amount Sanctioned | Date of Sanction | Outstanding Amount | Status of Account (Standard or NPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Tenzin Paldan | 1140000 | 29/03/2016 | 180,536.00 | Standard |
| 47 | Sanjeev Kumar | 400000 | 18/09/2015 | 143,121.00 | Standard |
| 48 | M/S Raizada Resorts | 33747000 | 21/01/16 | 33,435,394.00 | Standard |
| 49 | Gouri Devi | 200000 | 12/11/15 | 70,003.00 | Standard |
| 50 | Sh Sanjay Kumar Rana | 1000000 | 04/01/16 | 253,514.00 | Standard |
| 51 | Smt Paramjeet | 50000 | 15/12/2015 | 19,374.00 | Standard |
| 52 | Kaundal Trading Company. | 2500000 | 12/11/15 | 2,451,541.00 | Standard |
| 53 | Iqbal Singh Khera and Paul Khera | 45000000 | 23/02/16 | 34,796,026.00 | Standard |
| 54 | Prema Devi | 285000 | 09/11/15 | 228,551.00 | Standard |
| 55 | Mrs. SHANKUNTLA | 50000 | 25-06-2015 | 1,220.00 | Standard |
| 56 | Rana Industries | 1500000 | 20-02-2016 | 1,447,398.00 | Standard |
| 57 | Roop Lal | 300000 | 02/12/15 | 93,962.00 | Standard |
| 58 | Rana Industries | 1500000 | 20-02-2016 | 936,104.00 | Standard |
| 59 | AJ Gold & Silver Refinery | 120000000 | 21/01/16 | 119,965,147.00 | Standard |
| 60 | Mrs. MEENA DEVI | 95000 | 09/11/15 | 34,105.00 | Standard |
| 61 | Ravi Kumar | 90000 | 18/03/16 | 90,495.00 | Standard |
| 62 | Arun Kumar | 150000 | 03/03/16 | 151,635.00 | Standard |
| 63 | Mr. NEERAJ NEERAJ | 80000 | 23-02-2016 | 45,006.95 | Standard |
| 64 | Mr. SANDEEP KUMAR | 720000 | 17-07-2015 | 334,663.72 | Standard |
| 65 | . HEM RAJ | 855000 | 14-09-2015 | 395,021.00 | Standard |
| 66 | Brajeshwari Motors | 930000 | 19/09/15 | 16,921.00 | Standard |
| 67 | Seema Devi | 100000 | 10/02/16 | 2,820.00 | Standard |
| 68 | Bimla Devi | 300000 | 27-11-15 | 138,967.00 | Standard |
| 69 | Sawan Kumar | 720000 | 21/12/15 | 237,332.00 | Standard |
| 70 | Ranjeet Singh | 400000 | 02/03/16 | 281,059.00 | Standard |
| 71 | Luv Kumar | 800000 | 26/11/15 | 472,600.00 | Standard |
| 72 | Balbir Singh | 237000 | 17/09/2015 | 98,574.00 | Standard |
| 73 | MAMTA | 50000 | 13.10.15 | 34,591.00 | Standard |
| 74 | NIRMALA | 100000 | 14/07/2015 | 28,389.00 | Standard |
| 75 | KAMLA DEVI | 50000 | 08/09/15 | 50,000.00 | Standard |
| 76 | RITU DEVI | 100000 | 10/09/15 | 49,068.00 | Standard |
| 77 | Mamta Thakur | 570000 | 04/03/16 | 488,244.00 | Standard |
| 78 | SHER SINGH | 50000 | 09/06/15 | 19,498.00 | Standard |
| 79 | KRISHNA | 100000 | 27/06/2015 | 40,007.00 | Standard |
| 80 | Nidhi Sohal | 500000 | 18/03/16 | 240,984.00 | Standard |
| 81 | Kareena Industries | 700000 | 31-03-2016 | 411,948.00 | Standard |
| 82 | Mrs. TARA DEVI | 40000 | 17-09-2015 | .00 | Standard |
| 83 | Mr. DINU RAM | 80000 | 22-12-2015 | 37,092.00 | Standard |
| 84 | KAUSHLYA | 100000 | 30/7/2015 | 46,315.00 | Standard |
| 85 | DHUMAL STEEL IND | 380000 | 31/03/2016 | 242,171.00 | Standard |
| 86 | Sanjay Kumar | 400000 | 01/02/16 | 155,507.00 | Standard |
| 87 | Hotel Angel Inn | 33000000 | 22/04/15 | 28,732,616.50 | Standard |
| 88 | Narender Kumar | 50000 | 14/10/15 | 48,009.00 | Standard |
| 89 | Ajay Dhiman | 700000 | 26/11/15 | 447,805.00 | Standard |
| 90 | Brij Mohan | 400000 | 12/04/15 | 237,222.00 | Standard |
| 91 | Narender Kumar | 250000 | 10/12/15 | 104,780.00 | Standard |
| 92 | M/S Star Thermocol | 9000000 | 20/02/2016 | 5,581,459.00 | Standard |
| 93 | Karnail Singh | 200000 | 19/10/15 | 14,364.00 | Standard |
| 94 | M/S UR Sinter Pvt. Ltd. | 150000000 | 09/04/15 | 121,559,173.00 | Standard |
| 95 | M/S UR Sinter Pvt.Ltd. | 45000000 | 09/04/15 | 40,340,824.00 | Standard |
| 96 | Rajesh | 190000 | 22/09/15 | 110,002.00 | Standard |
| 97 | Nirmal Pathania | 2500000 | 15/06/15 | 481,537.00 | Standard |
| 98 | Kiran | 300000 | 30/01/16 | 188,183.00 | Standard |
| 99 | Jyoti Gupta | 500000 | 06/02/16 | 192,946.00 | Standard |
| 100 | Uttam Chand | 95000 | 15/12/15 | 35,516.00 | Standard |
| 101 | Arvind Kumar | 400000 | 28/09/15 | 135,143.00 | Standard |
| 102 | Aman Chaudhary | 400000 | 11/06/15 | 250,686.00 | Standard |
| 103 | Amt Gill | 190000 | 04/03/16 | 85,217.00 | Standard |
| 104 | M/S HOTE ABHINANDAN | 16200000 | 23/03/16 | 16,202,395.00 | Standard |
| 105 | Suneel Kumar | 150000 | 11/10/15 | 35,321.00 | Standard |
| 106 | Sh Dharam Chand | 40000 | 26/11/15 | 10,276.00 | Standard |
| 107 | Smt Aruna Devi | 40000 | 24/12/15 | .00 | Standard |
| 108 | Smt Shanta Devi | 100000 | 18/5/15 | 8,011.00 | Standard |
| 109 | Sh Ramesh Kumar | 40000 | 27/8/2015 | 11,693.00 | Standard |
| 110 | Sh Anil Kumar | 400000 | 16-09-2015 | 192,908.00 | Standard |
| 111 | DHUMAL STEEL IND | 600000 | 31/03/2016 | 598,367.00 | Standard |
| 112 | Sh Desh Raj | 200000 | 18-04-2015 | 83,798.00 | Standard |
| 113 | Sh Sanddep Kumar | 300000 | 09/08/15 | 139,425.00 | Standard |
| 114 | Suneel Kumar | 50000 | 11/10/15 | 34,093.00 | Standard |
| 115 | Vinod Kumar | 400000 | 19/01/16 | 216,651.00 | Standard |
| 116 | Sh Bihari Lal | 200000 | 07/10/15 | 97,701.00 | Standard |
| 117 | Ms Ritika Singh | 250000 | 10/02/16 | 155,892.00 | Standard |
| 118 | Sh Vinod Kumar | 200000 | 07/01/16 | 103,590.00 | Standard |
| 119 | Sh Rakesh Kumar | 65000 | 09/05/15 | 57,262.00 | Standard |
| 120 | Sh Rampal | 450000 | 28/01/2016 | 9,296.00 | Standard |
| 121 | Sh Rajeev Kumar | 50000 | 26/11/15 | 47,456.00 | Standard |
| 122 | Chamunda JLG | 120000 | 07/11/15 | 114,794.00 | Standard |
| 123 | Chinmay SHG | 32000 | 19/08/15 | 11,812.00 | Standard |
| 124 | Sh Mohonder Kumar | 50000 | 27/05/15 | 32,699.00 | Standard |
| 125 | Sh Ravi Parkash | 50000 | 04/06/15 | 44,365.00 | Standard |
| 126 | M/S Desh Raj | 150000 | 02/07/15 | 136,728.00 | Standard |
| 127 | Sh Gopal Dass | 50000 | 29/10/15 | 48,382.00 | Standard |
| 128 | The Bhungtial CAS | 60,00,000 | 05/08/15 | 61,29,549.00 | Standard |
| 129 | Shashi Paul | 100000 | 13/10/15 | 96,770.00 | Standard |
| 130 | Sunita | 600000 | 21.03.2016 | 394,186.00 | Standard |
| 131 | Pankaj | 1000000 | 11/03/16 | 504,758.00 | Standard |
| 132 | Sh Dhurav Kumar | 130000 | 11/09/15 | 72,782.36 | Standard |
| 133 | Sh Sanjeev Sharma | 500000 | 17/03/16 | 292,892.00 | Standard |
| 134 | Smt Neena Pardhan | 140000 | 12/08/15 | 36,630.00 | Standard |
| 135 | Smt Manju Devi | 235000 | 06/02/16 | 118,287.00 | Standard |
| 136 | Mrs. Reetu Sahnil | 185000 | 06/07/15 | 41,410.00 | Standard |
| 137 | Sh Parveen Kumar | 250000 | 22/05/15 | 88,571.00 | Standard |
| 138 | Sh Arvind Kumar | 1000000 | 13/05/15 | 753,856.00 | Standard |
| 139 | Sushil Kumar | 176000 | 20-10-2015 | 118,362.00 | Standard |
| 140 | Rama Sharma | 600000 | 23-03-2016 | 393,908.00 | Standard |
| 141 | Pankaj Kumar | 180000 | 06/11/15 | 70,542.00 | Standard |
| 142 | Pankaj Kumar | 50000 | 06/11/15 | 31,735.00 | Standard |
| 143 | Rakesh Kumar | 142000 | 21-11-2015 | 20,348.00 | Standard |
| 144 | Rakesh Kumar | 48000 | 21-11-2015 | 22,409.00 | Standard |
| 145 | Nainka Sharma | 142000 | 08/12/15 | 79,100.00 | Standard |
| 146 | Nainka Sharma | 48000 | 08/12/15 | 25,297.00 | Standard |
| 147 | Chunni Lal | 190000 | 11/12/15 | 107,946.00 | Standard |
| 148 | Chunni Lal | 95000 | 11/12/15 | 91,332.00 | Standard |
| 149 | Anjana Kumari | 142000 | 16-12-2015 | 74,947.00 | Standard |
| 150 | Anjana Kumari | 48000 | 16-12-2015 | 41,286.00 | Standard |
| 151 | Balbir Singh | 55000 | 26-02-2016 | 3,135.00 | Standard |
| 152 | Balbir Singh | 40000 | 26-02-2016 | 22,555.00 | Standard |
| 153 | Yagya Dutt | 1403000 | 09/03/16 | 834,533.00 | Standard |
| 154 | Yagya Dutt | 300000 | 09/03/16 | 285,482.00 | Standard |
| 155 | TRIBAL WEAVER H L COOP SOCIETY | 2500000 | 29/12/2015 | 342,407.00 | Standard |
| 156 | Mrs. RUMI DEVI | 50000 | 04/02/16 | 30,437.00 | Standard |
| 157 | Deepa Devi | 100000 | 01/06/15 | 64,958.00 | Standard |
| 158 | Simran SHG | 300000 | 12/06/15 | 68,818.00 | Standard |
| 159 | Usha Devi | 100000 | 24/07/2015 | 25,740.00 | Standard |
| 160 | Iqbal | 50000 | 16/10/2015 | 23,260.00 | Standard |
| 161 | Nilofar | 50000 | 16/10/2015 | 48,179.00 | Standard |
| 162 | Deepak Furniture & Joinery | 950000 | 22/12/2015 | 480,000.00 | Standard |
| 163 | Kirna Devi | 100000 | 21/01/2016 | 55,484.00 | Standard |
| 164 | Raza | 100000 | 20/02/2016 | 49,572.00 | Standard |
| 165 | Lata Devi | 50000 | 06/05/15 | 33,365.00 | Standard |
| 166 | Sheela Devi | 50000 | 06/09/15 | 28,497.00 | Standard |
| 167 | Tolu Devi | 100000 | 09/24/15 | 97,077.00 | Standard |
| 168 | Tolu Devi | 200000 | 09/25/15 | 182,987.00 | Standard |
| 169 | SAVITRA DEVI | 148000 | 04/12/15 | 126,559.00 | Standard |
| 170 | SANTOSH KUMARI | 100000 | 10/12/15 | 20,792.00 | Standard |
| 171 | JAGDISH CHAND | 50000 | 02/03/16 | 14,564.00 | Standard |
| | | | | **426,685,233.53** | |

## Account wise Detail of Loans sanctioned to industrial units in 2016-2017 (01-04-2016 to 31-03-2017)

| Sr. No. | Name of Borrower | Amount Sanctioned | Date of Sanction | Outstanding Amount | Status of Account (Standard or NPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desh Raj | 1000000 | 31/3/2017 | 253,578.00 | Standard |
| 2 | Vikash | 1500000 | 07/03/17 | 684,432.00 | Standard |
| 3 | Sh Arvind Saini | 1700000 | 28/03/17 | 1,612,439.00 | Standard |
| 4 | Smt Chhaya mankotia | 1688000 | 19/04/16 | 1,202,576.00 | Standard |
| 5 | Sh Dinesh Mahajan | 440000 | 16/03/17 | 348,436.00 | Standard |
| 6 | Sanjay kumar (composit loan) | 800000 | 05/12/16 | 596,509.00 | Standard |
| 7 | Sanjay kumar(composit loan) | 400000 | 28/03/17 | 388,691.00 | Standard |
| 8 | Pankaj | 700000 | 27-03-2017 | 658,952.00 | Standard |
| 9 | Pankaj | 300000 | 30-03-2017 | 301,219.00 | Standard |
| 10 | Charanjit | 15000000 | 5/12/16 | 15,648,272.00 | Standard |
| 11 | B S Industries | 6000000 | 24/03/2017 | 5,733,126.00 | Standard |
| 12 | Novatech Engineers | 1000000 | 01-09-2016 | 784,575.00 | standard |
| 13 | Novatech Engineers | 1500000 | 01-09-2016 | 1,496,967.00 | standard |
| 14 | Himco Steel India | 1700000 | 01-02-2017 | 1,365,923.00 | standard |
| 15 | Himco Steel India | 675000 | 01-02-2017 | 230,374.00 | standard |
| 16 | Una fabrication Work | 665000 | 30-03-2017 | 541,127.00 | standard |
| 17 | Una fabrication Work | 285000 | 30-03-2017 | 284,586.00 | standard |
| 18 | Jay Kumar | 760000 | 06/02/17 | 503,040.00 | Standard |
| 19 | Partap | 1000000 | 18/10/20 | 16 720,597.00 | Standard |
| 20 | HOTEL CHANDNI | 4000000 | 02/01/17 | 3,259,812.00 | Standard |
| 21 | HOTEL CHANDNI | 6000000 | 13/04/16 | 4,769,946.00 | Standard |
| 22 | Smt Seema | 300000 | 05/09/16 | 178,698.00 | Standard |
| 23 | Smt Seema | 100000 | 05/09/16 | 41,341.00 | Standard |
| 24 | Sh Rajeev Kumar | 285000 | 22/12/16 | 216,705.00 | standard |
| 25 | Smt Kusum Kumari | 380000 | 29/03/17 | 204,094.00 | Standrad |
| 26 | Divaskar Choudhary | 1053000 | 09/02/17 | 804,208.00 | Standard |
| 27 | Kangra Vehicleades | 10000000 | 15/07/16 | 7,534,916.00 | Standard |
| 28 | ANGELS INN RESORT | 10000000 | 27/03/17 | 9,998,418.00 | Standard |
| 29 | Sh Ramesh Chand | 2500000 | 27/09/16 | 2,225,062.00 | Standard |
| 30 | Sh Karan Singh | 1500000 | 24/03/17 | 625,602.00 | standard |
| 31 | Sh Madan Lal | 600000 | 04/08/16 | 249,906.00 | standard |
| 32 | Sh Kishan Chand | 1000000 | 11/05/16 | 344,824.00 | Standard |
| 33 | Sh Narinder Kumar | 1000000 | 01/12/16 | 1,028,092.00 | Standard |
| 34 | Sh Ramesh Kumar | 200000 | 02/08/16 | 135,550.00 | Standard |
| 35 | Sh Dalip Singh | 200000 | 09/07/16 | 160,386.00 | Standard |
| 36 | Sh Subhash Chand | 1000000 | 16/09/16 | 683,829.00 | Standard |
| 37 | Sh Bharat Bhushan | 300000 | 02/09/16 | 183,012.00 | Standard |
| 38 | Sh Sanjeev Kumar | 1000000 | 17/10/16 | 856,728.00 | Standard |
| 39 | Krishana Cement Products | 2000000 | 09/03/17 | 1,812,693.00 | Standard |
| 40 | Sh Pawan Kumar | 200000 | 25/05/16 | 101,086.00 | Standard |
| 41 | Sh Suraj Kumar | 250000 | 09/03/17 | 272,128.00 | Standard |
| 42 | Sh Jeewan Lal | 115000 | 24/01/17 | 118,023.00 | Standrad |
| 43 | Sh Sanjay Kumar | 115000 | 20/05/16 | 38,485.00 | standard |
| 44 | Sh Atul Vasudeva | 300000 | 04/10/16 | 249,431.00 | Standard |
| 45 | Sh Amar Singh Rana | 600000 | 05/07/16 | 502,381.00 | Standard |
| 46 | M/S Surindera Tragers | 1000000 | 10/06/16 | 515,150.00 | Standard |
| 47 | Sh Harjeet Singh | 200000 | 14/10/16 | 135,788.00 | Standard |
| 48 | Sh Anish Kumar Matta | 600000 | 18/02/17 | 488,076.00 | Standard |
| 49 | Sh Ankur Chaman | 1500000 | 21/03/17 | 1,218,189.00 | Standard |
| 50 | M/S Star Thermocol | 4000000 | 02/06/16 | 1,396,109.00 | standard |
| 51 | M/S J B B Stone crusher | 5000000 | 18/10/16 | 4,286,990.00 | standard |
| 52 | M/S J B B Stone crusher | 2500000 | 18/10/16 | 1,926,563.00 | standard |
| 53 | Sh Varun Rana | 150000 | 02/10/16 | 89,116.00 | Standard |
| 54 | RAKSHA DEVI | 4500000 | 21/11/16 | 4,638,066.00 | Standard |
| 55 | Sh Madan Lal | 200000 | 07/06/16 | 114,562.00 | Standard |
| 56 | Sh Amit Arora | 350000 | 20-09-2016 | 233,485.00 | Standard |
| 57 | Sh Vikram Chnad | 120000 | 16-09-2016 | 84,283.00 | Standard |
| 58 | Smt Neena Devi | 200000 | 29-03-2017 | 161,888.00 | Standard |
| 59 | Sh Sudesh Kumar | 200000 | 31/1/17 | 152,920.00 | Standard |
| 60 | Sh Manoj Kumar | 150000 | 04/05/16 | 95,588.00 | Standard |
| 61 | Sh Parveen Kumar | 200000 | 07/11/16 | 138,343.00 | Standard |
| 62 | Sh Amit Sharma | 200000 | 01/09/16 | 155,608.00 | Standard |
| 63 | Sh Deepak Kumar | 150000 | 14-02-2017 | 111,664.00 | Standard |
| 64 | Sh Rinku Kumar | 200000 | 22/07/2016 | 129,147.00 | Standard |
| 65 | Himachal Bakery | 50,00,000 | 13/01/2017 | 29,10,882/ | Standard |
| 66 | Deepa Chouhan | 380000 | 29/03/2017 | 318,521.00 | Standard |

शेष पृष्ठ 6 पर.....

# कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋण

.....पृष्ठ 5 का शेष

| Sr. No. | Name of Borrower | Amount Sanctioned | Date of Sanction | Outstanding Amount | Status of Account (Standard or NPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Suresh Kumar | 285000 | 14/03/2017 | 247,541.00 | Standard |
| 68 | Chhering Angdui | 570000 | 26/04/2016 | 315,774.00 | Standard |
| 69 | Rahul Thakur | 665000 | 12/07/16 | 483,322.00 | Standard |
| 70 | Lobzang Gyalson | 650000 | 31/01/2017 | 480,782.00 | Standard |
| 71 | Tandup Phunchog | 665000 | 20/03/2017 | 560,473.00 | Standard |
| 72 | Narbu Ram | 570000 | 28/03/2017 | 423,826.00 | Standard |
| 73 | Kesang Namgyal | 570000 | 28/03/2017 | 447,502.00 | Standard |
| 74 | Sonu Kumar | 40000 | 10/07/16 | 19,014.00 | Standard |
| 75 | Vijay Kumar | 600000 | 23.03.2017 | 304,209.00 | Standard |
| 76 | Vijay Kumar | 700000 | 31.03.2017 | 457,399.00 | Standard |
| 77 | Hotel Himalya Resort | 6000000 | 19/08/16 | 4,950,000.00 | Standard |
| 78 | Sh Rakesh Kalia | 15700000 | 09/02/17 | 13,811,423.00 | Standard |
| 79 | Hotel sagar View | 5000000 | 10/06/16 | 4,276,555.00 | Standard |
| 80 | Raj Hotel | 35000000 | 15/06/16 | 37,439,972.00 | Standard |
| 81 | Yudh Chnad Bains | 120000000 | 05/07/16 | 113,048,435.00 | Standard |
| 82 | Hotel Rajat Bangana | 15000000 | 05/12/16 | 15,648,272.00 | Standard |
| 83 | Hotel Mount Edge | 15000000 | 12/01/17 | 13,275,197.00 | Standard |
| 84 | Hotel Sarovar | 10000000 | 21/01/17 | 2,422,612.00 | Standard |
| 85 | Agustya Residency | 9000000 | 10/03/17 | 8,999,946.00 | Standard |
| 86 | Krishna Hans Raj Hotel | 6000000 | 27/01/17 | 6,264,973.00 | Standard |
| 87 | Surender Kumar | 1900000 | 11/01/17 | 1,413,742.00 | Standard |
| 88 | Sunil | 475000 | 12/01/17 | 410,048.00 | Standard |
| 89 | Ganpati H/L & H/C Wea CIS | 908000 | 30.09.16 | 894,851.00 | Standard |
| 90 | Mrs. GUDDI DEVI | 50000 | 20-05-2016 | 24,735.00 | Standard |
| 91 | Mrs. SUSHMA DEVI | 400000 | 26-05-2016 | 1,535.00 | Standard |
| 92 | Mr. SONTU RAM | 50000 | 04-07-2016 | 26,588.00 | Standard |
| 93 | Mrs. PHONCHOG DOLMA | 50000 | 03-10-2016 | 29,157.00 | Standard |
| 94 | Mrs. SUSHMA | 100000 | 23-02-2017 | 46,922.00 | Standard |
| 95 | Mrs. SUSHMA DEVI | 200000 | 26-05-2016 | 31,120.00 | Standard |
| 96 | Mr. RAM NATH | 1050000 | 26-07-2016 | 9,863.00 | Standard |
| 97 | Mr. RAKESH SHARMA | 550000 | 23-01-2017 | 333,374.00 | Standard |
| 98 | THE NARAYAN HL WEAVER SOCIETY | 188000 | 06-09-2016 | 212,269.00 | Standard |
| 99 | THE BHARTI STEEL WOOD FURNITU | 335000 | 04-11-2016 | 285,826.00 | Standard |
| 100 | INDIRA DEVI | 40000 | 27.09.16 | 19,958.00 | Standard |
| 101 | NARESH CHAND | 1000000 | 23.02.17 | 728,144.00 | Standard |
| 102 | BANITA | 100000 | 24.5.16 | 35,331.00 | Standard |
| 103 | JAMUNA | 100000 | 24.5.16 | 40,414.00 | Standard |
| 104 | SUSHEELA | 100000 | 26.5.16 | 34,880.00 | Standard |
| 105 | JEEVANA | 100000 | 26.5.16 | 47,461.00 | Standard |
| 106 | RAMNATH | 40000 | 20/05/2016 | 23,637.00 | Standard |
| 107 | SHYAM LAL | 50000 | 19/08/2016 | 32,936.00 | Standard |
| 108 | LAL CHAND | 40000 | 15/12/2016 | 32,140.00 | Standard |
| 109 | PARVATI | 185000 | 27/03/2017 | 148,137.00 | Standard |
| 110 | PARVATI | 100000 | 27/03/2017 | 103,126.00 | Standard |
| 111 | SHIV SHANKAR CON | 176000 | 06/12/16 | 205,865.00 | Standard |
| 112 | GORI SHANKAR WEAVER | 268000 | 20/12/2016 | 312,127.00 | Standard |
| 113 | KINNER ST/SC | 456840 | 10/03/17 | 517,817.00 | Standard |
| 114 | SARSAI H/L WE | 55830 | 10/03/17 | 63,281.00 | Standard |
| 115 | SARSAI H/L WE | 54174 | 10/03/17 | 61,404.00 | Standard |
| 116 | Lakhan Food Products | 3450000 | 21/07/2016 | 2,595,089.00 | Standard |
| 117 | Swadesh Kumar | 400000 | 06/01/17 | 372,367.00 | Standard |
| 118 | Shivani Thakur | 2000000 | 27/12/2016 | 797,975.00 | Standard |
| 119 | Ram Dai | 200000 | 20/02/2017 | 96,284.00 | Standard |
| 120 | Mohal Lal | 500000 | 22/03/2017 | 176,537.00 | Standard |
| 121 | Kushal Chand | 2500000 | 29/03/2017 | 950,870.00 | Standard |
| 122 | Mohal Harijan Coop Weav Soc | 200000 | 12/09/16 | 144,963.00 | Standard |
| 123 | New Himachal Coop Weav Soc Ltd | 120000 | 27-11-2016 | 82,385.00 | Standard |
| 124 | Bhutti Weavers Coop Soc Ltd | 35000000 | 01/02/17 | 28,285,911.00 | Standard |
| 125 | Tripta Sharma | 160000 | 12/08/16 | 139,017.00 | Standard |
| 126 | Pradeep sharma | 250000 | 21.01.2017 | 247,265.00 | Standard |
| 127 | Mrs. PREM LATA | 150000 | 27-05-2016 | 77,406.53 | Standard |
| 128 | M/s. THE HILL QUEEN WEAVERS CO | 188000 | 07/09/16 | 200,123.00 | Standard |
| 129 | THE GREAT HADIMBA SC WEAVERS | 177600 | 06/10/16 | 190,240.00 | Standard |
| 130 | THE GREAT HADIMBA SC WEAVERS | 1120000 | 06/10/16 | 1,285,877.00 | Standard |
| 131 | M/s. THE MANU WEAVER HL HC PCS | 800000 | 06/10/16 | 862,859.00 | Standard |
| 132 | M/s. THE NEW MANALI HL AND HC | 188000 | 06/10/16 | 183,942.00 | Standard |
| 133 | THE PREET WOMEN HC HL WEL SOC | 188000 | 07/02/17 | 187,672.00 | Standard |
| 134 | Harminder Singh | 300000 | 18-06-2016 | 188,070.00 | Standard |
| 135 | THE VARIETY WEAVERS SOCIETY | 60000 | 23/09/2016 | 70,854.00 | Standard |
| 136 | THE VARIETY WEAVERS SOCIETY | 48000 | 23/09/2016 | 56,687.00 | Standard |
| 137 | THE VARIETY WEAVERS SOCIETY | 720000 | 23/09/2016 | 681,085.00 | Standard |
| 138 | M/S JAGJEET SINGH | 270000 | 17/03/2017 | 210,504.00 | Standard |
| 139 | M/S JAGJEET SINGH | 180000 | 17/03/2017 | 141,173.00 | Standard |
| 140 | Mr. TAPE RAM | 50000 | 11/07/16 | 45,443.00 | Standard |
| 141 | HP STATE HL AND HC DEVELOPMENT | 4000000 | 20/03/2017 | 3,475,968.00 | Standard |
| 142 | Dolma Devi | 50000 | 04/04/16 | 22,583.00 | Standard |
| 143 | Hari Devi | 100000 | 05/04/16 | 105,959.00 | Standard |
| 144 | Hem Nath | 76000 | 13/05/16 | 61,104.00 | Standard |
| 145 | Hem Nath | 24000 | 13/05/16 | 5,489.00 | Standard |
| 146 | Chhina | 100000 | 26/05/2016 | 60,993.00 | Standard |
| 147 | Hazara Khtoon | 100000 | 03/11/16 | 18,291.00 | Standard |
| 148 | Sarswati S H G | 300000 | 16/12/2016 | 139,719.00 | Standard |
| 149 | Veer Nath S H G | 50000 | 25/11/2016 | 18,262.00 | Standard |
| 150 | Laxmi SHG | 100000 | 17/12/2016 | 67,168.00 | Standard |
| 151 | Abhnav Mineral Dhoop | 720000 | 22/03/2017 | 647,000.00 | Standard |
| 152 | Dassi Devi | 90000 | 24/1/2017 | 43,646.00 | standard |
| 153 | Raina H/L & H/C Weaver | 2500000 | 05/02/16 | 2,490,943.00 | Standard |
| 154 | Kirana Devi | 100000 | 10/06/16 | 99,145.00 | Standard |
| 155 | H.R.Enterprises | 115000 | 02/13/17 | 113,691.00 | Standard |
| 156 | SERAJ FRUIT & VEGITABLE MARKETING COOP SOC | 2000000 | 17/10/16 | 2,125,359.00 | Standard |
| 157 | TARA SINGH | 50000 | 16/06/16 | 26,862.00 | Standard |
| 158 | HARI SINGH | 50000 | 09/09/16 | 18,832.00 | Standard |
| 159 | BALBIR SINGH | 400000 | 20/03/2017 | 348,236.00 | Standard |
| 160 | THE SERAJ GARH MAHILA HL HC | 184000 | 08/09/16 | 178,532.00 | Standard |
| 161 | THE KOTHI CHAINI MAHILA | 188000 | 08/09/16 | 124,346.00 | Standard |
| 162 | THE DLAIDA COOP AGRI SERVICE | 257600 | 29/9/16 | 202,064.00 | Standard |
| 163 | | | | **365,009,536.53** | |
| 164 | Sh Sanjeev Lakhanpal | 10000000 | 09/05/16 | 10,673,843.00 | NPA |
| 165 | Dhiman Automobiles | 500000 | 06/04/16 | 416,394.00 | NPA |
| 166 | Sh Vikas Makkar | 200000 | 15/09/16 | 162,111.00 | NPA |
| 167 | Ramshila Weavers Co-op Society | 168000 | 06/09/16 | 202,864.00 | NPA |
| 168 | Tripura H/L & H/C Wea CIS | 340000 | 30.09.16 | 405,018.00 | NPA |
| 169 | Anandini village Resorts | 30000000 | 19/08/16 | 32,140,215.00 | NPA |
| 170 | Kimat Ram | 1100000 | 07/01/17 | 1,181,680.00 | NPA |
| 171 | Gumat Ram | 960000 | 18/07/2016 | 1,002,864.00 | NPA |
| 172 | Sat Pal | 40000 | 07/04/16 | 32,286.00 | NPA |
| 173 | Ajay Kumar | 40000 | 07/04/16 | 28,062.00 | NPA |
| 174 | Pradeep Kumar | 40000 | 10/07/16 | 32,372.00 | NPA |
| 175 | Sh Sunny Kumar | 200000 | 02/10/16 | 118,270.00 | NPA |
| 176 | HOTEL RS BALVEDRE | 45000000 | 18/06/16 | 46,240,213.00 | NPA |
| 177 | HOTEL RS BALVEDRE | 5000000 | 18/06/16 | 5,150,788.00 | NPA |
| 178 | Smt Kavita Bhatia | 750000 | 21/11/16 | 645,220.00 | NPA |
| 179 | M/S C Z Village Bloosoms Resort | 1000000 | 14/03/17 | 83,410,660.00 | NPA |
| 180 | Sh Sameer Bhatia | 600000 | 18/02/17 | 508,999.00 | NPA |
| 181 | THE PARCHA HL HC WEAVERS | 197600 | 23/9/16 | 114,704.00 | NPA |
| 182 | TIRTHAN VALLEY HL HC WEAVERS | 177600 | 27/9/16 | 204,681.00 | NPA |
| 183 | THE JIBHI WOOL WORKERS HL | 184000 | 05/10/16 | 216,994.00 | NPA |
| 184 | THE CHETER COP AGRI SERV | 97600 | 13/10/16 | 103,267.00 | NPA |
| | | | | **182,991,505.00** | |

## Account wise Detail of Loans sanctioned to industrial units in 2017-2018 (01-04-2017 to 31-03-2018)

| Sr. No. | Name of Borrower | Amount Sanctioned | Date of Sanction | Outstanding Amount | Status of Account (Standard or NPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poonam Devi | 1615000 | 30/3/2018 | 1,192,961.00 | Standard |
| 2 | Kiran | 2500000 | 07/10/17 | 1,944,535.00 | Standard |
| 3 | Chander Mani | 495000 | 30/12/17 | 484,828.00 | Standard |
| 4 | Moti Lal | 3000000 | 26/03/18 | 817,191.00 | Standard |
| 5 | Nirmla Devi | 95000 | 06/09/17 | 47,820.00 | Standard |
| 6 | Usha Devi | 550000 | 07/03/18 | 537,000.00 | Standard |
| 7 | Virender Sharma | 1700000 | 04/11/17 | 1,121,169.00 | Standard |
| 8 | GS board Mills | 2000000 | 19/06/17 | 1,959,455.00 | Standard |
| 9 | Kannav Biocreation Pvt Ltd | 12000000 | 28-09-2017 | 12,235,271.00 | Standard |
| 10 | Rajeev Kumar | 1350000 | 28/09/17 | 1,127,698.00 | Standard |
| 11 | Organic Valley | 82250000 | 08/08/17 | 40,237,029.00 | standard |
| 12 | Ambika Enterprises | 1710000 | 30.03.2018 | 1,744,966.00 | standard |
| 13 | Ambika Enterprises | 540000 | 30.03.2018 | 25.00 | standard |
| 14 | Kuldeep Soni | 630000 | 31/07/17 | 132,499.00 | Standard |
| 15 | Smt Gouri devi | 100000 | 12/08/17 | 88,985.00 | Standard |
| 16 | Sh Sunny Mahajan | 100000 | 09/12/17 | 81,097.00 | Standard |
| 17 | Sh Sunny Mahajan | 619766 | 09/12/17 | 511,696.00 | Standard |
| 18 | Sh Satpal | 200000 | 28/09/17 | 174,022.00 | Standrad |
| 19 | ANGELS INN RESORT | 15000000 | 27/06/17 | 15,015,063.00 | Standard |
| 20 | Sh Sandeep Thapa | 1000000 | 09/11/17 | 860,555.00 | standard |
| 21 | HARI SINGH & SUJEET KUMAR | 20000000 | 18/08/17 | 16,646,054.00 | Standard |
| 22 | ANIL KAPOOR JOGINDER SAIN | 9000000 | 14/09/17 | 7,111,624.00 | Standard |
| 23 | Sh Jaipal Singh | 1000000 | 24/10/17 | 1,013,658.00 | Standard |
| 24 | PRADEEP SHARMA | 10000000 | 30/01/18 | 1,192,959.00 | Standard |
| 25 | OM PRAKASH | 5440000 | 30/01/18 | 3,705,083.00 | Standard |
| 26 | Sh ram Singh & Neeru | 2500000 | 09/03/18 | 629,487.00 | Standard |
| 27 | Smt Rita Rajpal | 200000 | 28/07/17 | 173,296.00 | Standard |
| 28 | Sh Onkar Chand | 400000 | 13/10/17 | 174,049.00 | Standard |
| 29 | Sh Surinder Kumar | 250000 | 05/01/18 | 179,691.00 | Standard |
| 30 | Sh Surinder Kuamr | 250000 | 05/01/18 | 143,454.00 | Standard |
| 31 | Sh Aman Kumar | 50000 | 29/01/18 | 47,973.00 | Standard |
| 32 | Smt Anju Devi | 100000 | 15/01/18 | 98,521.00 | Standard |
| 33 | Smt Anjana | 100000 | 25/01/18 | 92,838.00 | Standard |
| 34 | Smt Rajni | 100000 | 30/01/18 | 84,187.00 | Standard |
| 35 | Smt Saroj | 100000 | 06/02/18 | 90,668.00 | Standard |
| 36 | Sh Samir Dogra | 900000 | 25/09/17 | 796,863.00 | Standrad |
| 37 | Sh Deep Chand | 100000 | 11/10/17 | 94,693.00 | Standrad |
| 38 | Sh Rakesh Kumar | 50000 | 27/02/18 | 50,593.00 | standard |
| 39 | M/S NIRVANA HEIGHTS | 2300000 | 31/07/17 | 1,821,277.00 | standard |
| 40 | Mr Rajesh Kumar | 150000 | 22/02/18 | 148,248.00 | standard |
| 41 | Smt Meenakshi | 500000 | 29/03/18 | 500,498.00 | standard |
| 42 | Sh Sunny Barjatia | 800000 | 18/10/17 | 789,471.00 | standard |
| 43 | Sh Vishal | 1500000 | 16/11/17 | 542,698.00 | standard |
| 44 | Sh Pawan Kumar | 2000000 | 30/06/17 | 1,629,736.57 | Standard |
| 45 | Sh Brij Mohan Sharma | 2000000 | 30/06/17 | 1,873,907.03 | Standard |
| 46 | Smummet Crockery & Manufacture | 1500000 | 05/12/17 | 480,925.00 | Standard |
| 47 | M/S S Industry | 1500000 | 18/10/17 | 1,495,405.00 | Standard |

शेष पृष्ठ 7 पर.....

# कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋण

.....पृष्ठ 6 का शेष

| Sr. No. | Name of Borrower | Amount Sanctioned | Date of Sanction | Outstanding Amount | Status of Account (Standard or NPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Sh Adiytah Sharma | 500000 | 17/04/17 | 402,803.00 | Standard |
| 49 | Sh Om Dutt | 360000 | 21/12/17 | 352,442.00 | Standard |
| 50 | MS AGGARWAL JEWELLERS | 800000 | 28/03/17 | 449,132.00 | Standard |
| 51 | M/S Bakes & Baker | 1500000 | 28/09/17 | 1,188,300.00 | Standard |
| 52 | Mangal Singh | 1900000/- | 15/11/2017 | 1774828/- | standard |
| 53 | M/S Ganpati Stone Crusher | 12500000 | 18/05/17 | 11,941,950.00 | standard |
| 54 | M/S Ganpati Stone Crusher | 3500000 | 18/05/17 | 3,152,946.00 | standard |
| 55 | Naveen | 285000 | 09/12/17 | 241,454.00 | Standard |
| 56 | Naveen | 285000 | 09/12/17 | 223,729.00 | Standard |
| 57 | Amar Febrication | 1235000 | 09/07/17 | 1,216,889.00 | Standard |
| 58 | Sh Raj Kuamr Verma | 70000 | 18-04-2017 | 46,282.00 | Standard |
| 59 | Sh Parmodh Kumar | 250000 | 25-04-2017 | 209,097.00 | Standard |
| 60 | Sh Manjeet | 100000 | 08/01/17 | 68,465.00 | Standard |
| 61 | Smt Shailza Chauhan | 100000 | 04/01/18 | 86,286.00 | Standard |
| 62 | Sh Vijay Kumar | 200000 | 12/02/18 | 191,641.00 | Standard |
| 63 | Deepak Dhaba | 285000 | 15/09/17 | 240,793.00 | Standard |
| 64 | SONI FASHION BOUTIQUE | 475000 | 29/09/17 | 378,485.00 | Standard |
| 65 | PRITI SHARMA BOUTIQUE | 285000 | 28/09/17 | 225,490.00 | Standard |
| 66 | Sh Kuldeep Chand | 80000 | 21-09-2017 | 53,468.00 | Standard |
| 67 | Sh Kuldeep Chand | 20000 | 21-09-2017 | 15,627.00 | Standard |
| 68 | Sushma Dairy | 500000 | 17-08-2017 | 199,000.00 | Standard |
| 69 | Sh Vinod Kumar | 200000 | 03/08/17 | 164,167.00 | Standard |
| 70 | Sh Abhishek Verma | 150000 | 30-08-2017 | 115,859.00 | Standard |
| 71 | Sh Rakesh Guleria | 160000 | 22-09-2017 | 140,498.00 | Standard |
| 72 | Sh Chandervir Paul | 200000 | 06/01/18 | 176,780.00 | Standard |
| 73 | Sh Rajneesh Kumar | 200000 | 19-03-2018 | 187,985.00 | Standard |
| 74 | Sh Rinku Kumar | 150000 | 17/10/2017 | 135,424.00 | Standard |
| 75 | Sh Jagdesh Chand | 200000 | 27/09/17 | 192,348.00 | Standard |
| 76 | Sh Pappu Ram | 100000 | 05/09/17 | 95,220.00 | Standard |
| 77 | Smt Arti | 70000 | 27/10/17 | 55,220.00 | Standard |
| 78 | Sh Madan Lal | 200000 | 01/09/17 | 134,246.00 | Standard |
| 79 | Sh Joginder Kumar | 950000 | 13.11.17 | 828,930.00 | Standard |
| 80 | Sh Vijay Kumar | 475000 | 16.11.17 | 337,005.00 | Standard |
| 81 | Smt Pooja Devi | 190000 | 20.11.17 | 121,744.00 | Standard |
| 82 | Sh Vipan Kumar | 450000 | 16.11.17 | 389,527.00 | Standard |
| 83 | Smt Sunita Kumari | 380000 | 02/03/18 | 280,444.00 | Standard |
| 84 | Sh Trilik Chnad | 188100 | 22.03.18 | 130,881.00 | Standard |
| 85 | Ashok Kumar | 900000 | 05/12/17 | 852,038.00 | Standard |
| 86 | Sher Singh | 95000 | 28/03/2018 | 91,347.00 | Standard |
| 87 | Bhagat Ram | 285000 | 17/08/2017 | 260,309.00 | Standard |
| 88 | VEENA THAKUR | 1,00,00,000 | 17/05/2017 | 1,03,35,689 | Standard |
| 89 | Lobzang Gyalson | 570000 | 20/03/2018 | 471,515.00 | Standard |
| 90 | Sonam Tandup | 570000 | 20/03/2018 | 246,995.00 | Standard |
| 91 | Nawang Kheytup | 380000 | 20/03/2018 | 302,889.00 | Standard |
| 92 | Angchuk Dorje | 475000 | 26/03/2018 | 300,489.00 | Standard |
| 93 | Poonam | 2375000 | 21.09.2017 | 2,217,541.00 | standrard |
| 94 | sushma Path | 1450000 | 14.08.2017 | 889,684.00 | standrard |
| 95 | Pankaj Kumar | 2250000 | 24.11.2017 | 2,195,013.00 | standrard |
| 96 | Ishan chand | 1000000 | 24.03.2017 | 642,894.00 | standrard |
| 97 | Sunita | 700000 | 25.03.2018 | 617,044.00 | standrard |
| 98 | Sunita | 600000 | 03/03/18 | 145,769.00 | standrard |
| 99 | Suresh & Neeraj | 16600000 | 02/05/17 | 8,362,549.00 | Standard |
| 100 | M/S Raizada Resorts | 20000000 | 22/06/17 | 21,167,094.00 | Standard |
| 101 | Mahadev Cold Stores | 35000000 | 22/05/17 | 16,172,491.00 | Standard |
| 102 | Meera Sharma | 295000 | 10/08/17 | 247,313.00 | standard |
| 103 | Sunita Devi | 1710000 | 15.01.18 | 1,450,006.00 | standard |
| 104 | Anjna | 190000 | 13.03.18 | 185,037.00 | Standard |
| 105 | Rajat Kant | 450000 | 26.03.18 | 440,763.00 | standard |
| 106 | Bharat fertilizer & Agro Chemical | 499000 | 26.03.18 | 466,836.00 | Standard |
| 107 | Luxmi Printing Press | 855000 | 27.03.18 | 688,466.00 | Standard |
| 108 | Whispring Resorts | 110000000 | 04/09/17 | 33,476,322.00 | Standard |
| 109 | Angu Dobhi H/L & H/C Wea CIS | 240000 | 31.08.17 | 244,409.00 | Standard |
| 110 | Chanderkhani H/L & H/C Wea CIS | 720000 | 01/11/17 | 655,915.00 | Standard |
| 111 | Manali Valley Live stock-& other pro Coop Soc | 640000 | 25.01.18 | 602,744.00 | Standard |
| 112 | Mrs. SUSHMA | 500000 | 27-07-2017 | 405,831.00 | Standard |
| 113 | Mr. DILA RAM | 95000 | 07-09-2017 | 69,510.00 | Standard |
| 114 | Mr. SANJEEV KUMAR | 160000 | 14-09-2017 | 134,275.00 | Standard |
| 115 | Mr. BIR SINGH | 50000 | 11-10-2017 | 46,405.00 | Standard |
| 116 | Mrs. SUNITA MANEPA | 570000 | 20-11-2017 | 535,318.00 | Standard |
| 117 | Mrs. SUSHMA | 300000 | 27-07-2017 | 275,090.00 | Standard |
| 118 | Mr. DILA RAM | 100000 | 07-09-2017 | 53,392.00 | Standard |
| 119 | Mrs. SUNITA MANEPA | 190000 | 20-11-2017 | 506.00 | Standard |
| 120 | Mr. HARISH KUMAR | 200000 | 28/11/2017 | 198,160.00 | Standard |
| 121 | Mr. HARDYAL | 350000 | 07-11-2017 | 320,454.00 | Standard |
| 122 | THE SEOBAG HL HC HARIJAN COOP | 192000 | 05-12-2017 | 179,970.00 | Standard |
| 123 | THE SEOBAG HL HC HARIJAN COOP | 48000 | 05-12-2017 | 44,721.00 | Standard |
| 124 | BANDROL WOMEN WEAVAR SOCIETY | 108000 | 16-01-2018 | 104,041.00 | Standard |
| 125 | BANDROL WOMEN WEAVAR SOCIETY | 147000 | 16-01-2018 | 123,946.00 | Standard |
| 126 | MEENA KUMARI | 500000 | 12/03/18 | 395,225.00 | Standard |
| 127 | RAVI | 1425000 | 08/11/17 | 1,002,320.00 | Standard |
| 128 | M/s Naggar Fruit Processing Industry | 10700000 | 9/04/2017 | 9,879,708.00 | Standard |
| 129 | THE JAGRITI WOMEN HL AND HC | 428000 | 29/05/17 | 426,560.00 | Standard |
| 130 | SHIV SHAKTI HL AND HC COOP | 236000 | 08/06/17 | 155,365.00 | Standard |
| 131 | HEM LATA | 40000 | 13/06/2017 | 30,963.00 | Standard |
| 132 | MANI RAM | 150000 | 22/05/2017 | 131,220.00 | Standard |
| 133 | BEGMU | 50000 | 12/02/18 | 49,158.00 | Standard |
| 134 | TRIPURA H/L | 108000 | 07/04/17 | 122,526.00 | Standard |
| 135 | KATRAIN SC/ST | 60000 | 24/4/2017 | 67,717.00 | Standard |
| 136 | KATRAIN SC/ST | 240000 | 19/4/2017 | 268,634.00 | Standard |
| 137 | BARAGRAN H/LH/C | 240000 | 11/07/17 | 269,826.00 | Standard |
| 138 | DHARA WOOL | 240000 | 26/9/2017 | 254,154.00 | Standard |
| 139 | SHIVA G WEAV | 240000 | 26/9/2017 | 249,996.00 | Standard |
| 140 | PATLIKUHAL WEAVERS | 240000 | 06/10/17 | 213,526.00 | Standard |
| 141 | BAGA H/L | 240000 | 05/02/18 | 244,141.00 | Standard |
| 142 | Prem Lata Thakur | 2000000 | 23/10/2017 | 757,057.00 | Standard |
| 143 | Gagna Devi | 2000000 | 28/11/2017 | 1,976,324.00 | Standard |
| 144 | Vishal Ahuja | 2000000 | 15/12/2017 | 516,576.00 | Standard |
| 145 | Toli Devi | 700000 | 12/12/17 | 370,167.00 | Standard |
| 146 | BHAnoo Hospital Pvt Ltd | 500000 | 03/03/18 | 451,927.00 | Standard |
| 147 | New Himachal Coop Weav Soc Ltd | 300000 | 30/08/2017 | 228,899.00 | Standard |
| 148 | Himachal H/L & H/C Weav Coop soc | 300000 | 10/04/17 | 253,552.00 | Standard |
| 149 | Mohal Harijan Weav Coop Soc Ltd | 300000 | 15/02/2018 | 243,388.00 | Standard |
| 150 | Kant H/L & H/C Coop Soc Ltd | 400000 | 16/02/2018 | 352,912.00 | Standard |
| 151 | Chandravati | 160000 | 19.08.2017 | 142,307.00 | Standard |
| 152 | Heeravati | 200000 | 12/03/18 | 161,476.00 | Standard |
| 153 | M/s. THE MANU WEAVER HL HC PCS | 1900000 | 29/11/2017 | 1,918,167.00 | standard |
| 154 | M/s. THE DHANSERI GALICHA HL W | 585000 | 15/04/2017 | 485,490.00 | standard |
| 155 | M/s. HIMALAYAN BODH WOMENS GAL | 240000 | 02/11/17 | 251,293.00 | standard |
| 156 | Mr. THE KAUSHLA HC HL WEAVERS | 108000 | 24-05-2018 | 108,271.00 | standard |
| 157 | Mr. THE KAUSHLA HC HL WEAVERS | 132000 | 24-05-2018 | 132,331.00 | standard |
| 158 | Seema Rani | 100000 | 05/10/17 | 36,904.00 | standard |
| 159 | Ambika Namkeen | 600000 | 17-02-2018 | 487,015.00 | standard |
| 160 | Ambika Namkeen | 500000 | 17-02-2018 | 395,174.00 | standard |
| 161 | Surbhi Steel | 4000000 | 29-03-2018 | 3,947,637.00 | standard |
| 162 | ROYAL HARIJAN WEAVER COOP SOC | 240000 | 25/04/2017 | 105,499.00 | standard |
| 163 | THE KAILASH H L WEAVERS SOCIE | 240000 | 18/09/2017 | 227,221.00 | standard |
| 164 | THE TRIBAL WOMEN GROMDYOG WEA | 240000 | 28/12/2017 | 254,132.00 | standard |
| 165 | THE TRIBAL WOMEN GROMDYOG WEA | 112000 | 28/12/2017 | 118,596.00 | standard |
| 166 | Mrs. GUDI DEVI | 50000 | 27/10/2017 | 39,539.00 | Standard |
| 167 | HP STATE HL AND HC DEVELOPMENT | 800000 | 03/11/17 | 822,388.00 | Standard |
| 168 | The Vikas H/L & H/C Weavers | 240000 | 20/10/2017 | 220,335.00 | Standard |
| 169 | Maa Naina Mahila S H G | 50000 | 29/08/2017 | 38,940.00 | Standard |
| 170 | Bhuvneshwari Hydro Pvt Ltd | 124500000 | 03/10/17 | 29,289,000.00 | Standard |
| 171 | Samridhi H/L & H/C | 1800000 | 29/03/2018 | 540,000.00 | Standard |
| 172 | Laxmi SHG | 50000 | 08/08/17 | 23,952.00 | Standard |
| 173 | Durvasa Rishi SHG | 100000 | 30/10/2017 | 40,279.00 | Standard |
| 174 | Ram Saran | 40000 | 05/15/17 | 21,690.00 | Standard |
| 175 | Sita Ram | 55000 | 12/12/17 | 44,692.00 | Standard |
| 176 | Puran Chand | 360000 | 10/05/17 | 298,355.00 | Standard |
| 177 | Puran Chand | 400000 | 10/06/17 | 320,186.00 | Standard |
| 178 | SHIVANI BUNKAR PROD. CUM SALES COOP INDUSTRIAL SOCIETY | 1200000 | 26/05/17 | 1,341,943.00 | Standard |
| 179 | THE SHANGI HARIGEN MAHILA | 300000 | 13/11/17 | 249,487.00 | Standard |
| 180 | THE MINIYASHI CAS | 480000 | 06/02/18 | 337,625.00 | Standard |
| 181 | BHAWANI WEAVERS PRIODCT | 908000 | 27/7/17 | 191,950.00 | Standard |
| 182 | THE VACHHOT COOP AGRI SER | 60000 | 26/9/17 | 558,448.00 | Standard |
| 183 | THE VACHHOT COOP AGRI SER | 180000 | 26/9/17 | 166,216.00 | Standard |
| 184 | THE MANGLORE COOPAGRI SERVICE | 100000 | 26/9/17 | 99,896.00 | Standard |
| 185 | THE MANGLORE COOP AGRI SERVICE | 80000 | 26/9/17 | 76,712.00 | Standard |
| 186 | THE BHAWANI WEAVERS PRODUCT | 720000 | 10/10/17 | 666,195.00 | Standard |
| 187 | THE TARGALI COOP AGRI SERVICE | 100000 | 11/10/17 | 75,026.00 | Standard |
| 188 | KAMLESH THAKUR | 600000 | 15/3/18 | 563,159.00 | Standard |
| 189 | | | | **305,886,736.60** | |
| 190 | THE RADHIKA KINNAR HARIJAN WEAVERS COOP SOC. | 240000 | 25/05/2017 | 254,342.00 | NPA |
| 191 | THE RADHIKA KINNAR HARIJAN WEAVERS COOPSOC. | 60000 | 25/05/2017 | 63,576.00 | NPA |
| 192 | MOHINI WOOL WORKERS IND | 60000 | 09/10/17 | 63,890.00 | NPA |
| 193 | MOHINI WOOL WORKERS IND | 180000 | 09/10/17 | 191,669.00 | NPA |
| 194 | M/S Sai Industries | 4000000 | 30/12/17 | 4,050,768.00 | NPA |
| 195 | Anandini Village Resorts | 20000000 | 22/06/17 | 21,205,097.00 | NPA |
| | | | | **25,829,342.00** | |

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

# क्या सरकार के फैसले से गैर कृषक की बंदिश हट पायेगी उठा सवाल

**शिमला/शैल।** जयराम सरकार ने 25.7.18 को राजस्व विभाग की ओर से प्रदेश के सारे मण्डलायुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में गैर हिमाचली अधिकारियों /कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवम् भू-सुधार अधिनियम 1972की धारा 118 के अन्तर्गत भूमि क्रय किये जाने कीअनुमति प्रदान करने बारे मार्ग दर्शन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा अधिकारी /कर्मचारी प्रदेश में अपने आवास हेतु भूमि क्रय करना चाहता है तो वह इसका पात्र है। यदि उसकी पात्रता के तहत उसके पुत्र/पुत्री भी आवास के लिये भूमि क्रय करना चाहते हैं तो वह भी इसके पात्र होंगे। भले ही वह प्रदेश के बाहर ही क्यों न रह रहे हों। इसके लिये उन्हे प्रदेश में तीस वर्ष तक कार्य करने का प्रमाणपत्र नही देना होगा।

सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों /अधिकारियों के लिये बड़ी राहत करार दिया जा रहा है। लेकिन उन्हे प्रदेश के राजस्व नियमों के जानकारों के मुताबिक इस फैसले से कोई बड़ी राहत मिलने जैसी बात नही है। क्योंकि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिमाचली हो या नही इस कानून की धारा 118 के तहत भूमि क्रय करने की अनुमति सरकार से ले सकता है। अब तक हज़ारों लोग ऐसी अनुमति लेकर प्रदेश में ज़मीने खरीद हुए हैं। प्रदेश में किसी भी गैर कृषक को ज़मीन खरीदने पर पावंदी है चाहे वह हिमाचली है या नही। ऐसे व्यक्ति को धारा 118 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता है और वह सरकार के इस फैसले के बाद भी यथास्थिति लागू रहती है। क्योंकि इस फैसले से कोई गैर कृषक-कृषक नही बन जायेगा। ऐसे में यदि सरकार प्रदेश में कार्यरत गैर हिमाचलीयों पर से गैर कृषक की बंदिश हटाना चाहती है तो उसके लिये 1972 के एक्ट में विधानसभा के अन्दर संशोधन लाना पड़ेगा। क्योंकि इस एक्ट के तहत 1975 में बने नियमों में संशोधन करके कृषक का दर्जा नही दिया जा सकता।

स्मरणीय है कि जब जयराम सरकार ने कार्यभार संभाला था तब इस आश्य का एक ब्यान दिया था कि सरकार 1972 के मुजारियत और भुसुधार एक्ट में संशोधन करना चाहती है। बजट सत्र में सरकार के इस ब्यान पर सदन में काफी हंगामा हुआ था और कांग्रेस ने वाक्आउट तक किया था। इस परिदृश्य में सरकार का यह फैसला एक और विवाद को जन्म दे सकता है कि जब सरकार गैर हिमाचली अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को यह सुविधा देना चाहती है तो उन लोगों को क्यों नही जो प्रदेश में लम्बे समय कारोबार कर रहे हैं और यहीं के बाशिंदे हो गये हैं।

गौरतलब है कि ऐसे कारोबारी लोग लम्बे अरसे से यह मांग भी करते आ रहे हैं। इन लोगों ने धारा 118 को प्रदेश उच्च न्यायालय में 1995 से लेकर 2010 तक छः अलग-अलग याचिकाएं डालकर चुनौती भी दी है लेकिन इन सभी याचिकाओं के फैसलों में उच्च न्यायालय ने धारा 118 की वैधता को स्वीकार किया है। लेकिन इसके बाद एक और याचिका पर सितम्बर 2016 में प्रदेश उच्च न्यायालय की जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेशवर ठाकुर की पीठ ने सरकार को यह निर्देश दिये थे कि This court deems it fit and proper to direct the state government to make suitable amendments to Section 118 of the HP Tenancy and Land Reforms Act,1972 read with HP Tanancy and Land Reforms Rules, 1975 in order to Facilitate to purchase any land (agricultural and non -agricultural) in the state by non- agriculturist Himachalis residing in the state for decades, prior to the date of commencement of the HP Tenancy and Land Reforms Act, 1972 within a period of 90 days from today"

लेकिन उच्च न्यायालय के इन निर्देशों की अनुपालना के लिए अब तक कोई कदम नही उठाये गये है। आज भी जब सरकार ने यह फैसला लिया है तब शायद इन निर्देशों का कोई संज्ञान नही लिया गया है। धारा 118 के तहत गैर कृषकों पर लगाई गयी बंदिश हर सरकार के लिये एक बड़ा मुद्दा रही है। लेकिन इसे कोई भी हटा नही पाया है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि यह धारा लगायी क्यों गयी थी। इस एक्ट के उद्देश्यों की घोषणा में कहा गया है STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS:" As a result of the re-organisation of the erstwhile state of Punjab in November, 1966,some areas were integrated in Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966.

There are different enactments regarding tenancy and agrarian reforms in force in new and old areas of the Pradesh immediately before 1st November, 1966, the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 is in force which is a progressive legislation about the security of tenures of tenants and their other rights. in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act,1966,however, occupancy tenants have been vested with proprietary rights under two Acts on the subject namely, the Punjab Occupancy tenants (Vesting of Proprietary rights) Act, 1953 and the Pepsu Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1954. in the old areas the occupancy tenants have to apply for ownership under section 11 of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act.Ithas therefore been considered necessary to unify the various laws relating to tenancies as in force in the pradesh and to provide for a measure of land reforms to remove disparities.

**Restrictions have been imposed to purchase land by the non-agriculturists to avoid concentration of wealth in the hands of non-agriculturists moneyed class.** The Bill is to achieve the above objects

.इसके बाद 1987 में इस एक्ट की धारा 104 में संशोधन करके इसे कड़ा किया गया था। धारा 104 में संशोधन धारा 113 के परिप्रेक्ष में किया गया था। इस संशोधन के उद्देश्यों में भी यह कहा गया है कि Statement of Objects and Reasons of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Bill 1987 provides as under:

STAREMENT OF OBJECTS AND REASONS:" Under the existing provisions contained contained in the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1971 the right, title and interest of the Government in the lands owned by it and leased out to a person vest in tenants. It is imperative that the proprietary rights in Government lands, by and large regenerated through public funds, should not pass to private persons, it has, therefore, become necessary to make suitable amendment in section 104 of the said Act, Under the provison to section 113 of the said Act. The land in respect of which proprietary rights have been acquired by a non-occupancy tenant, can be transferred by way of sale, mortgage gift or otherwise only for productive purposes with the permission of the Collector. In odrder to aviod misuse of this provision and to ensure that such permission should be accorded rarely and only under genuine cricumstances, it has been decided that the said permission be given by the State Government alone Section 118 of the principal Act, which restricts transfer of land to non-agriculturists, does not apply to the transfer of lands situated in urban areas, nor does it apply to transfer of lands not used for purposes subservient to agriculture. The lands classified as "Gair-mumkin makan" "Gair mumkin dhank" can be transferred in favour of non-agriculturists and thus the provisions as they exist leave a loop hole in law which is designed to prevent the transfer of land to non-agriculturists. it has therefore, become necessary to make suuitable amendments in the existing law. The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

इस परिदृश्य में सरकार का अब लिया गया फैसला अपने में बेमानी हो जाता है। क्योंकि इससे गैर कृषक की बंदिश नही हटती है और जब तक की यह बंदिश नही हटती है ऐसे फैसले से किसी को कोई लाभ नही मिल पायेगा। सरकार के इस फैलसे से जो यह माना जा रहा है कि इससे गैर हिमाचली अधिकारियों/ कर्मचारियों और उनके पुत्र/ पुत्री को भूमि क्रय में लाभ मिलेगा इसके लिये जानकारों के मुताबिक सरकार को इस फैसले में संशोधन करना पड़ेगा।



1019
01/08/2018

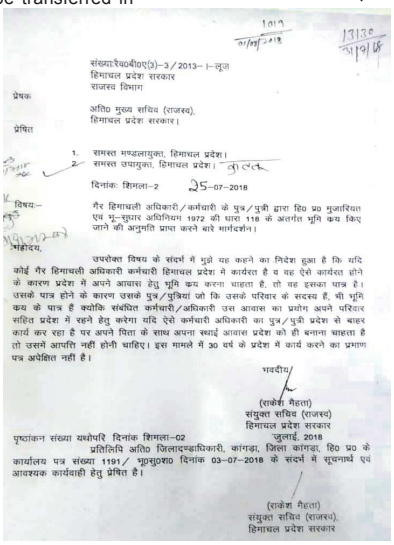

13130
31/7/18

संख्याःरैव0बी0ए(3)–3/2013–I–लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

अति0 मुख्य सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–2 25–07–2018

विषयः– गैर हिमाचली अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री द्वारा हि0 प्र0 मुजारियत एवं भू–सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के अंतर्गत भूमि कय किए जाने की अनुमति प्राप्त करने बारे मार्गदर्शन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि कोई गैर हिमाचली अधिकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है व वह ऐसे कार्यरत होने के कारण प्रदेश में अपने आवास हेतु भूमि कय करना चाहता है, तो वह इसका पात्र है। उसके पात्र होने के कारण उसके पुत्र/पुत्रियां जो कि उसके परिवार के सदस्य हैं, भी भूमि कय के पात्र हैं क्योकि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी उस आवास का प्रयोग अपने परिवार सहित प्रदेश में रहने हेतु करेगा यदि ऐसे कर्मचारी अधिकारी का पुत्र/पुत्री प्रदेश से बाहर कार्य कर रहा है पर अपने पिता के साथ अपना स्थाई आवास प्रदेश को ही बनाना चाहता है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 30 वर्ष के प्रदेश में कार्य करने का प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं है।

भवदीय,
(राकेश मैहता)
संयुक्त सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि दिनांक शिमला–02 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि अति0 जिलादण्डाधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के कार्यालय पत्र संख्या 1191/ भू0सु0श0 दिनांक 03–07–2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(राकेश मैहता)
संयुक्त सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार

# पानी कनैक्शन के लिये नही है नगर निगम के पास कोई नियम

**शिमला/शैल।** नगर निगम शिमला में प्लानिग एरिया के अन्दर घरेलू उपयोग, व्यवसायिक उपयोग और निर्माणों के लिये पानी का कनैक्शन प्राप्त करने के लिये कोई भी स्वीकृत नियम नही हैं। यह जानकारी नगर निगम ने डा. बंटा को आरटीआई के तहत उपलब्ध करवाई हैं। नगर निगम शिमला में पिछले दिनो हुआ पेयजल संकटअन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में रहा हैं। क्योंकि इस संकट पर एक पखवाड़े तक प्रदेश उच्च न्यायालय ने लगातार मामले की सुनवाई की और कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय करोल ने स्वंय सड़क पर निकलकर इस समस्या की गंभीरता की व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी हासिल की। यही नही शिमला में लोगों को किन दरों पर पानी की सप्लाई की जा रही है इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। विधानसभा तक को निगम की ओर से यह जानकारी दी गयी है कि पानी का बिल मीटर रिडिंग पर दिया जा रहा है जबकि यह बिल फ्लैट रेट पर दिये जा रहे हैं।

आम आदमी की यह धारणा है कि निगम घरेलू, व्यवसायिक और भवन निर्माण कार्यो के लिये अलग- अलग दरों पर बिल देता है एक से अधिक कनैक्शन नही दिये जाते है। लेकिन यह सारी धारणा आरटीआई में आयी जानकारी के बाद एकदम धराशायी हो जाती हैं। होटल लैण्डमार्क के संद्धर्भ में मांगी गयी जानकरी में यह सूचना आयी है कि पानी का कनैक्शन देने के लिये प्लानिग एरिया मे नगर निगम शिमला के पास कोई स्वीकृत निमय नही हैं। सबकुछ संबंधित अधिकारी की ईच्छा पर ही निर्भर करता है। होटल लैण्डमार्क को पांच कनैक्शन दिये गये है जिसमे कुछ कनैक्शन होटल लैण्डमार्क के नाम पर तथा कुछ टी. आर. शर्मा और विनोद अग्रवाल के नाम पर है। एक ही होटल में अगल-अगल नामों पर पाये गये कनैक्शनों से यह प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में ही कोई नियम नही है।

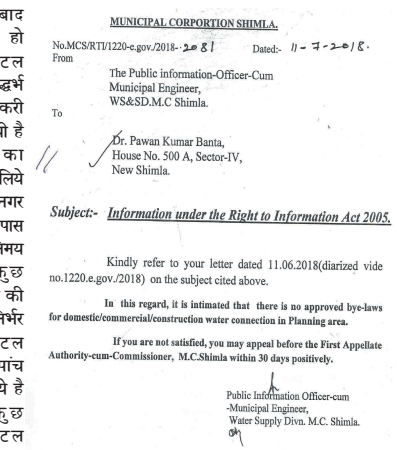



MUNICIPAL CORPORTION SHIMLA.

No.MCS/RTI/1220-e.gov./2018-2081 Dated:- 11-7-2018.

From

The Public information-Officer-Cum
Municipal Engineer,
WS&SD.M.C Shimla.

To

Dr. Pawan Kumar Banta,
House No. 500 A, Sector-IV,
New Shimla.

*Subject:-* *Information under the Right to Information Act 2005.*

Kindly refer to your letter dated 11.06.2018(diarized vide no.1220.e.gov./2018) on the subject cited above.

**In this regard, it is intimated that there is no approved bye-laws for domestic/commercial/construction water connection in Planning area.**

**If you are not satisfied, you may appeal before the First Appellate Authority-cum-Commissioner, M.C.Shimla within 30 days positively.**

Public Information Officer-cum
-Municipal Engineer,
Water Supply Divn. M.C. Shimla.